

वार्षिक प्रतिवेदन

2020-21



राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी
नई दिल्ली

वार्षिक प्रतिवेदन

2020–21



राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी
एनएएससी, देवप्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली – 110 012, भारत

अगस्त 2021

प्रस्तावना

अकादमी के सम्मानित अध्येताओं के समक्ष वर्ष 2020–21 के दौरान संचालित गतिविधियों एवं उपलब्धियों का सारांश प्रस्तुत करना मेरे लिए गर्व की बात है। इस अवधि के दौरान हमने अप्रत्याशित व्यवधानों एवं परिवर्तनों से पूर्ण एक नई दुनिया देखी है। मुझे यह बताते हुए संतोष हो रहा है कि कृषि-क्षेत्र में इन अभूतपूर्व चुनौतियों के बावजूद अध्येताओं (फैलोशिप) ने राष्ट्र के सक्रिय थिंक टैंक के रूप में अकादमी की भूमिका को सफल बनाने की दिशा में समर्पित भाव से कार्य किया।

इस अवधि के दौरान, जब डिजिटल संचार, संप्रेषण का एक आम माध्यम हो गया है, अकादमी ने आवश्यकता के अनुरूप अपने आपको समायोजित किया है। अकादमी ने राष्ट्रीय स्तर पर 16 कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें विचार मंथन (ब्रेनस्टॉर्मिंग) सत्रों, नीतिगत कार्यशालाओं, विशेषज्ञों की बैठक एवं विशेषज्ञ परामर्श बैठकों के साथ-साथ व्याख्यान भी प्रस्तुत किए गए। विचार मंथन का मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि के समसामयिक मुद्दों पर आधारित था, जिसमें नीति निर्माताओं, सरकार, उच्च शिक्षा संस्थानों, किसानों एवं अन्य हितधारकों के लिए कार्रवाई के साथ विशिष्ट सिफारिशें तैयार कीं गईं। इन आयोजनों के फलस्वरूप 09 नीति पत्र और नीति संक्षेप तैयार किए गए।

स्थापना दिवस समारोह को अकादमी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक माना जाता है। इस कार्यक्रम से सभी अध्येताओं (फैलोशिप) को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों के साथ जुड़ने और अकादमी के दृष्टिकोण के अनुरूप नई रणनीतियों को अपनाने हेतु अपने विचारों को साझा करने का अवसर प्राप्त होता है। कोविड के प्रचलित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए स्थापना दिवस को इसके वास्तविक स्वरूप में मनाने के बजाय “कोविड 19: प्रभाव एवं कृषि में नई सामान्य प्रक्रिया” विषय पर एक वर्चुअल पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। इसमें कृषि के क्षेत्र में कोविड –19 संकट के दुष्परिणामों तथा महामारी के बाद के कृषि विकास को बनाए रखने के लिए तकनीकी एवं नीतिगत समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें भारतीय कृषि से संबंधित मुद्दों और स्थायी खाद्य प्रणाली को सुनिश्चित करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपायों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

इस कठिन दौर में अकादमी के क्षेत्रीय केंद्रों (चैप्टरों) द्वारा किए गए प्रयास विशेष तौर पर उल्लेखनीय हैं। क्षेत्रीय चैप्टरों द्वारा 29 से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विचार मंथन सत्रों एवं वेबिनार आदि के माध्यम से वैज्ञानिक और शैक्षणिक विचारों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने में इन कार्यक्रमों को अत्यधिक सफल पाया गया। इनमें से कुछ कार्यक्रम छात्रों पर केंद्रित थे। हाई स्कूल,



स्नातक एवं स्नातकोत्तर के छात्रों को कृषि के विभिन्न पहलुओं जैसे ग्रामीण जैव-उद्यमिता, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कृषि में उपलब्ध अवसरों के साथ-साथ स्वास्थ्य, पोषण एवं पर्यावरण से संबंधित अन्य समकालीन मुद्दों से अवगत कराया गया। मैं, क्षेत्रीय चैप्टर के सभी संयोजकों के बहुमूल्य प्रयासों के लिए उनकी सराहना करता हूं तथा उन्हें धन्यवाद देता हूं।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में एक थिंक टैंक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए अकादमी ने कई महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर महत्वपूर्ण और सामयिक जानकारी प्रदान की है जिस पर सरकार द्वारा सक्रिय तौर पर विचार हो रहा है।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अकादमी ने नास –समाचार के सभी अंक नियमित रूप से प्रकाशित किए तथा नास ईयरबुक 2021 एवं नास वार्षिक प्लानर को भी समय पर प्रकाशित किया। नास जर्नल के सभी अंकों को समय पर प्रकाशित करने के अथव प्रयासों के लिए मैं, एग्रीकल्चरल रिसर्च के प्रधान संपादक, प्रोफेसर अनुपम वर्मा को विशेष धन्यवाद देता हूं।

मैं नास के तत्कालिक पूर्व अध्यक्ष डॉ. पंजाब सिंह, डॉ. जे. सी. कत्याल और डॉ. अनिल के. सिंह (01.01.2021 से), उपाध्यक्ष, डॉ. पी. के. जोशी और डॉ. के. सी. बंसल (1.1.2021 से), सचिव, डॉ. यू. एस. सिंह, विदेश सचिव, डॉ. पी. एस. बिरथल एवं डॉ. मालविका ददलानी (01.01.2021 से), संपादक, डॉ. आर. के. जैन, कोषाध्यक्ष को उनके मार्गदर्शन और योगदान के लिए धन्यवाद देता हूं। निवर्तमान पदाधिकारियों और कार्यकारी परिषद के सदस्यों (31.12.2020 तक) यथा डॉ. ए. के. श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष, डॉ. अनिल के. सिंह, सचिव, डॉ. कुमुमाकर शर्मा, संपादक एवं सदस्यों – डॉ. बी. एस. द्विवेदी, डॉ. अश्विनी कुमार, डॉ. वी. प्रकाश और डॉ. डी. डी. पात्रा को विशेष धन्यवाद देता हूं।

नास सचिवालय के सभी सहयोगी – श्री संचल बिलग्रामी (31.05.2020 तक), श्री मिराजुदीन, सुश्री मीनू तिवारी, श्री पी. कृष्णा, श्री उमेश राय, श्री जय सिंह, श्री कमल सिंह एवं श्री बनवारी लाल सचिवालय की सभी दैनिक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। डेयर तथा भाकृअनुप द्वारा दी गई वित्तीय एवं लॉजिस्टिक सहायता के लिए उनका भी सादर आभार व्यक्त करता हूं।



(टी. महापात्र)

अध्यक्ष

विषय-सूची

प्रस्तावना	iii
अकादमी के बारे में	1
वैज्ञानिक गतिविधियां	2
विचार मंथन सत्र/नीतिगत कार्यशालाएं/परामर्शी बैठकें	2
15वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस – ऊर्जा एवं कृषि : 21वीं सदी में चुनौतिया	15
क्षेत्रीय चैप्टर	16
बारापानी चैप्टर	16
बैंगलुरु चैप्टर	16
भोपाल चैप्टर	16
कोयम्बटूर चैप्टर	17
कटक चैप्टर	17
हैदराबाद चैप्टर	17
करनाल चैप्टर	18
कोलकता चैप्टर	18
लखनऊ चैप्टर	19
लुधियाना चैप्टर	19
पुणे चैप्टर	19
वाराणसी चैप्टर	20
सम्पर्क	27
संस्थागत सदस्यता	28
उत्कृष्टता की पहचान (2021)	29
नए अध्येता	29
प्रवासी अध्येता (फैलो)	31
एसोशियेटशिप	31
विदेशी फैलो	31

द्विवार्षिक 2019–2020 के दौरान अकादमी द्वारा प्रदत्त पुरस्कार	32
संस्थापना दिवस एवं वार्षिक आम सभा	34
नव निर्वाचित अध्येताओं (फैलो) द्वारा प्रस्तुतीकरण	34
अध्यक्षीय संबोधन	34
संस्थापना दिवस समारोह	35
27वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) के कार्यवृत्त के अंश	37
अध्येताओं / एसोसियेट का प्रवेश समारोह	37
सामान्य विचार विमर्श	37
प्रकाशन	38
नीति / स्टेटस / नीतिगत शोधपत्र	38
संक्षिप्त नीतिपत्र (पालिसी ब्रीफ)	38
न्यूजलेटर	38
जर्नल (स्प्रिंजर इडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित)	38
अन्य प्रकाशन	38
विभिन्न कार्यक्रम एवं बैठकें	39
नववर्ष सम्मेलन	39
क्षेत्रीय चैप्टरों के संयोजकों की बैठक	40
कार्यकारी परिषद की बैठक	41
जर्नल स्कोर समिति	45
नास द्वारा परामर्शी सेवाएं	46
वर्ष 2021 के लिए नियोजित कार्यक्रम	47
वित्तीय विवरण	48
आभार	48
अनुलग्नक	
लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	49
लेखों का लेखापरीक्षित विवरण	52
कार्यकारी परिषद	54
संक्षिप्तियों की सूची	56

अकादमी के बारे में

स्वर्गीय प्रो. बी. पी. पाल, एफआरएस की दूर एवं व्यापक दृष्टि से प्रेरित होकर, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (नास) की स्थापना 1990 में फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, इंजीनियरिंग और सामाजिक विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों के कृषि वैज्ञानिकों के लिए एक संवादात्मक मंच के रूप में की गई थी ताकि कृषि एवं कृषि आधारित आजीविका, कृषि अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रसार जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जा सके तथा शासन के विभिन्न स्तरों पर नीति-निर्माताओं और अन्य हितधारकों को साक्ष्य-आधारित जानकारी (इनपुट) की सुविधा प्रदान की जा सके। अकादमी द्वारा कृषि विज्ञान से संबंधित समसामयिक मुद्दों पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस, सम्मेलनों, संगोष्ठियों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और विचार-मंथन सत्रों का आयोजन किया जाता है और उन्हें सहायता प्रदान करने के अलावा विभिन्न मंचों में कृषि अनुसंधान, शिक्षा और प्रसार की दृश्यता पर विचार विमर्श किया जाता है।

यह अकादमी, कृषि विज्ञान पर एक जीवंत राष्ट्रीय स्तर की संस्था के रूप में उभरी है। अकादमी के अध्येताओं में भारत और विदेश दोनों से कृषि और संबद्ध विज्ञान के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए ख्याति प्राप्त विशिष्ट व्यक्ति शामिल हैं।

उद्देश्य

- पारितंत्रीय रूप से टिकाऊ, आर्थिक रूप से जीवंत एवं सामाजिक रूप से न्यायसंगत कृषि को बढ़ाना।
- वैज्ञानिकों द्वारा कृषि क्षेत्र में संचालित वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्टता की पहचान एवं उसका समर्थन।
- होनहार वैज्ञानिकों को उनके कार्य में प्रगति हेतु अनिवार्य सुविधाएं प्रदान करना।
- देश एवं विश्व वैज्ञानिक समुदाय के साथ विभिन्न संस्थानों तथा संगठनों के शोधकर्ताओं के बीच संपर्क को बढ़ावा देना।
- विज्ञान-नीति इंटरफेस को मजबूत करने के लिए किसानों, खेती और कृषि रूपांतरण के महत्वपूर्ण मुद्दों के अंतर-विषयी विश्लेषण को व्यवस्थित एवं संचालित करना और विकास के लिए कृषि अनुसंधान, विस्तार एवं शिक्षा की प्रगति हेतु दस्तावेजों का प्रकाशन।
- कृषि विज्ञान की प्रगति हेतु वित्तीय एवं वृत्तिदान को सुरक्षित रखना एवं उसका प्रबंधन।
- उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अन्य प्रासंगिक गतिविधियों का संचालन।

अकादमी की संरचना

- महा निकाय :** अकादमी का यह निकाय इसके सभी अध्येताओं (फैलो) से मिलकर बनता है।
- कार्यकारी परिषद (ईसी) :** अकादमी की नीति एवं निर्णय हेतु यह प्रमुख निकाय है। अकादमी के प्रशासन एवं क्रियाकलापों के विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन में कई समितियां इसकी सहायता करती हैं।
- क्षेत्रीय चैप्टर :** अकादमी के 12 क्षेत्रीय केंद्र (चैप्टर) बड़ापानी, बैंगलुरु, भोपाल, कोयम्बटूर, कटक, हैदराबाद, करनाल, कोलकाता, लखनऊ, लुधियाना, पुणे तथा वाराणसी में कार्य कर रहे हैं।

वैज्ञानिक गतिविधियां

विचार मंथन सत्र/ नीतिगत कार्यशालाएं/ परामर्शी बैठकें

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान निम्नलिखित विचार—मंथन सत्रों/नीतिगत कार्यशालाओं/परामर्शी बैठकों का आयोजन किया गया।

क्रम सं.	विषय/शीर्षक	संयोजक/सह—संयोजक	तिथि
1.	स्थापना दिवस समारोह—कोविड 19 : प्रभाव एवं कृषि में नई सामान्यता	डॉ. पी के. जोशी एवं डॉ. पी. एस. विरथल	5 जून, 2020
2.	गैर—गोजातीय दूध की क्षमता	डॉ. एम. एस. चौहान	29 जून, 2020
3.	खाद्य सुरक्षा एवं जलवायु कार्रवाई हेतु मृदा जैविक कार्बन में वृद्धि	डॉ. चौधरी श्रीनिवास राव एवं डॉ. अनिल कुमार सिंह	21 अगस्त, 2020
4.	प्रति—सूक्ष्मजीवीय प्रतिरोधिता (एएमआर)	डॉ. ए. के. श्रीवास्तव एवं डॉ. अनिल कुमार अरोड़ा	29 अगस्त, 2020
5.	जैविक विविधता अधिनियम की समीक्षा : नियम एवं दिशानिर्देश	डॉ. कुलदीप सिंह	1 सितंबर, 2020
6.	टिकाऊ ईधन एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम हेतु गन्ना आधारित एथेनॉल उत्पादन	डॉ. बख्शी राम	18 सितंबर, 2020
7.	एक विश्व—एक स्वास्थ्य	डॉ. ए. के. श्रीवास्तव, डॉ. आर. एस. औलख एवं डॉ. आर. के. सिंह	19 सितंबर, 2020

क्रम सं.	विषय / शीर्षक	संयोजक / सह-संयोजक	तिथि
8.	पाँच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था हेतु कृषि एवं खाद्य नीति	डॉ. सुरेश पाल	14 अक्टूबर, 2020
9.	भारत में उच्च कृषि शिक्षा का रूपांतरण	प्रोफेसर आर. बी. सिंह	20 अक्टूबर, 2020
10.	आलू बीज उत्पादन में नवोन्मेष एवं उनका अनुप्रयोग	डॉ. एस. के. चक्रबर्ती	27 अक्टूबर, 2020
11.	शहरी एवं अर्ध-शहरी कृषि में अपशिष्ट जल (वेस्ट-वाटर) का उपयोग	डॉ. जे. सी. डागर	17 नवंबर, 2020
12.	भारत में प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त टमाटरों का प्रजनन	डॉ. ए. टी. सदाशिव	24 नवंबर, 2020
13.	भारतीय पशुधन एवं कुक्कुट के सीमापार संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु आपातकालीन तैयारी	डॉ. परिमल राय	19 दिसंबर, 2020
14.	कृषि के रूपांतरण हेतु संविदा खेती – चुनौतियां एवं भावी मार्ग	डॉ. अंजनी कुमार	10 मार्च, 2021
15.	जैवखेती हेतु पराजीनी कुक्कुट की संभावना	डॉ. तरुण कुमार भट्टाचार्य	15 मार्च, 2021
16.	अदृश्य भूख एवं पोषणिक सुरक्षा को संबोधित करने हेतु जैवसंपूरण : वर्तमान स्थिति एवं भावी मार्ग	डॉ. यू. एस. सिंह	26 मार्च, 2021

गैर-गोजातीय दूध की क्षमता (संयोजक : डॉ. उम. उस. चौहान)

गैर-गोजातीय दूध एवं उससे बने उत्पाद अपने पोषण एवं स्वास्थ्य लाभों के कारण लोगों के आहार में दिनोंदिन महत्व प्राप्त कर रहे हैं। गैर-गोजातीय दूध और इसके स्वास्थ्य गुणों पर विचार करने तथा इसके उत्पादन में स्थायी वृद्धि लाने पर विचार करने के लिए एक विचार मंथन सत्र का ऑनलाइन आयोजन किया गया। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (नास) के अध्यक्ष डॉ. टी. महापात्र ने सत्र की अध्यक्षता की। अपने प्रारंभिक संबोधन में उन्होंने मानव स्वास्थ्य-लाभ हेतु इनमें उपस्थित जैव-सक्रियताओं के लक्षण वर्णन के



अलावा, गोजातीय एवं गैर-गोजातीय प्रजातियों के दूध की गुणवत्ता में नस्लों के अंतर को स्पष्ट करने के लिए अनुसंधान करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

चर्चा में सामने आए कुछ प्रमुख मुद्दे और उन पर की गई सिफारिशें इस प्रकार थीं:

गैर-गोजातीय दूध से बने उत्पादों की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जबरदस्त मांग है और ये उत्कृष्ट खाद्य (सुपरफूड) के रूप में उभरे हैं।

- ‘मेटाजीनोमिक्स’ एवं ‘कल्वरोमिक्स’ विधियों का उपयोग करते हुए सभी गैर-गोजातीय प्रजातियों की सूक्ष्मजीवी संरचना (माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोफाइल) पर प्राप्त सूचनाओं को संकलित करके ‘गैर-गोजातीय मिल्कबायोम और मेटाबोलोम’ पर अनुसंधान को तेज करने की आवश्यकता है।
- गैर-गोजातीय दूध उत्पादन को सुदृढ़ करने के लिए दूध माइक्रोबायोटा एवं कुछ चुनिंदा जीवाणु प्रजातियों के संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण पर एक व्यापक सूची तैयार करने की आवश्यकता है।
- गैर-गोजातीय दूध और दुग्ध उत्पाद पौष्टिक रूप से बेहतर हैं और इनका व्यापारिक एवं आर्थिक मूल्य भी बहुत अधिक होता है। इसलिए, उनकी गुणवत्ता की निगरानी के लिए बायोमार्कर के रूप में उपयोग में लाए जाने वाले विशिष्ट मेटाबोलाइट्स की पहचान महत्वपूर्ण है।

खाद्य सुरक्षा उत्तर जलवायु कार्बवार्ड (उक्तशन) हेतु मृदा जैविक कार्बन को बढ़ाने हेतु नीतियां (संयोजक : डॉ. चौधरी श्रीनिवास राव उत्तर डॉ. अनिल के. सिंह)

खाद्य सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता तथा जलवायु अनुकूलन एवं शमन में मृदा जैविक कार्बन (एसओसी) के महत्व पर चर्चा हेतु अकादमी के अध्यक्ष डॉ. टी. महापात्र की अध्यक्षता में एक विचार मंथन सत्र आयोजित किया गया।



इस चर्चा के फलस्वरूप निम्नलिखित सिफारिशें उभर कर सामने आईं:

1. भूमि संरक्षण द्वारा तथा किसानों की भूमि-उपयोग प्रथाओं के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण के साथ समग्र भूमि प्रबंधन द्वारा उत्पादन में होने वाले नुकसान को कम करना।
2. किसानों को कार्बन-स्मार्ट कृषि पद्धतियों को अपनाने पर वित्तीय सहायता (सब्सिडी) प्रदान करना।
3. ‘कार्बन प्रच्छादन पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना’ एवं कार्बन प्रच्छादन हेतु ‘किसानों के नवोन्मेष एवं परस्पर शिक्षण पर एक प्लेटफॉर्म का सृजन करना।

सूक्ष्मजीवरोधी प्रतिरोधिता (संयोजक: डॉ. उ. के. श्रीवास्तव, शह संयोजक: डॉ. अनिल कुमार अरोड़ा)

रोगाणुरोधी प्रतिरोधिता (एएमआर) नैदानिक, जैविक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय घटकों से प्रभावित एक सीमा-पार चुनौती है और यह मनुष्यों, पालतू / गैर-पालतू पशुओं तथा परितंत्र को प्रभावित करती है। यह वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा एवं विकास के सबसे गंभीर खतरे के रूप में उभरी है। एएमआर से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए डॉ. टी. महापात्र की अध्यक्षता में एक विचार मंथन सत्र का आयोजन किया गया। डॉ. महापात्र ने विभिन्न क्षेत्रों में सूक्ष्मजीवरोधी प्रतिरोधिता के सृजन हेतु घटकों को लक्षित करने के प्रयासों को पुनः व्यवस्थित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

विचार मंथन के दौरान की गई प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थीं:

1. लक्षित बीमारियों के लिए इंसानों तथा पशु चिकित्सा में एंटीबायोटिक दवाओं के विवेकपूर्ण और सही उपयोग पर एक नीति तथा कम गंभीर लेकिन संवेदनशील एंटीबायोटिक के साथ मानक एवं साक्ष्य-आधारित उपचार, दिशानिर्देश और प्रोटोकॉल तुरंत विकसित किए जाने चाहिए।
2. राष्ट्रीय स्तर पर एक 'एएमआर नियामक मंच' स्थापित किया जाना चाहिए तथा इंसानों, पशुओं व पर्यावरण इंटरफेस पर रोगाणुरोधी प्रतिरोधिता की जांच और उसका पता लगाने के लिए एक समन्वित 'क्षेत्रीय नेटवर्क कार्यक्रम' शुरू किया जाना चाहिए।

जैविक विविधता अधिनियम की समीक्षा : नियम एवं दिशानिर्देश (संयोजक : डॉ. कुलदीप सिंह)

जैविक विविधता के संरक्षण, इसके विभिन्न घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों के समान बंटवारे के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जैविक विविधता अधिनियम (बीडीए)-2002 को मुख्य रूप से प्रख्यापित किया गया था। तथापि, यह महसूस किया गया कि अधिनियम के उद्देश्यों को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक अधिनियम में मौजूद कमियों को दूर नहीं किया जाता। बीडीए-2002 के महत्व को देखते हुए एक विचार मंथन सत्र का आयोजन किया गया।

विचार-मंथन सत्र से निम्नलिखित सिफारिशें सामने आईं:

1. कृषि जैव-विविधता से संबंधित सभी क्रियाकलापों को विनियमित करने की



- शक्तियां एवं जिम्मेदारी जैवविविधता (बीडी) अधिनियम की धारा 16 के तहत सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, भाकृअनुप को सौंपी जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 'डेयर' को कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता के लिए अधिदेश प्राप्त है।
2. भारत एवं अन्य साधन प्रदाता देशों के बीच पारस्परिकता के आधार पर कृषि जैव-विविधता के आनुवंशिक संसाधनों के आदान-प्रदान हेतु एक राष्ट्रीय तंत्र सृजित करने की आवश्यकता है।
 3. पीपीवीएफआरए, 2001 और बीडीए, 2002 को प्राथमिकता के आधार पर सुसंगत बनाना।
 4. कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों, पशुओं, कीटों, मछलियों और सूक्ष्मजीवों के लिए कृषि जैव-विविधता की रिपॉजिटरी (भंडार) का विस्तार किया जाए।
 5. अंतर-सरकारी, अंतर-क्षेत्रीय और भारत-सीजीआईएआर संस्थानों के बीच सहयोग को एनबीए विनियमों से छूट प्रदान की जाए।
 6. गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए विदेशी शोधकर्ताओं तक माइक्रोबियल कल्चर तक पहुंच (एक्सेस) को सुगम बनाया जाए।
 7. राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल अनुक्रम सूचना (डीएसआई) की पहुंच और उससे प्राप्त लाभ को साझा करने के मुद्दे पर सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है।

टिकाऊ ईंधन इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम हेतु गन्ना-आधारित इथेनॉल उत्पादन (संयोजक : डॉ. बख्शी राम)

उपरोक्त विषय पर डॉ. मंगला राय एवं डॉ. टी. महापात्र की सह-अध्यक्षता में एक विचार मंथन सत्र का आयोजन किया गया। डॉ. महापात्र ने बायोइथेनॉल उत्पादन एवं प्रसंस्करण तथा मूल्य शृंखला के सृजन हेतु अक्षय ऊर्जा के लक्ष्यों, मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) पर प्रकाश डाला।

सत्र की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थीं:

1. इथेनॉल ईंधन की कीमतें तय करने के लिए उत्पादन से समिश्रण तक इथेनॉल की परिवहन लागत को शामिल किया जाए।
2. बेहतर अर्थव्यवस्था (इकोनॉमी) के लिए एथेनॉल की कीमत को सफेद चीनी की कीमत से 1.6 गुना ज्यादा तय किया जाए।
3. चीनी के सीजन में कम रिकवरी फेज के दौरान इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए।
4. ऑफ-सीजन के दौरान इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने की किस्मों को अपनाया और बढ़ावा दिया जाए।

एक विश्व - एक स्वास्थ्य (संयोजक : डॉ. उ. के. श्रीवास्तव उवं सह संयोजक : डॉ. आर. उस. औलख उवं डॉ. आर. के. रिंह)

पशुजन्य (जूनोटिक) रोगों के प्रति सामयिक एवं प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए एक सार्थक रणनीति के रूप में स्थिति के सटीक एवं साझा आकलन के आधार पर एक बहु-क्षेत्रीय 'एक स्वास्थ्य' दृष्टिकोण की वकालत की जाती रही है। एक विश्व—एक स्वास्थ्य की रणनीति और व्यापक नीति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अकादमी द्वारा डॉ. टी. महापात्र की अध्यक्षता में एक विचार—मंथन सत्र का आयोजन किया गया। अपने प्रारंभिक संबोधन में डॉ. महापात्र ने एक विश्व — एक स्वास्थ्य विजन को साकार करने की दिशा में बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक वैश्विक गठबंधन बनाने की प्रासंगिकता और महत्व पर जोर दिया।

प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थीं:

1. एमबीबीएस, बीबीएससी एवं एएच, बी.एससी. (कृषि) एवं बी.एससी. (पर्यावरण विज्ञान) के स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम में "वन हेल्थ" संकल्पना को शामिल करना अपेक्षित है।
2. पशुजनित (जूनोटिक) एवं खाद्य—जनित रोगों के नियंत्रण एवं उन्मूलन के लिए एक व्यापक जन अभियान चलाया जाना चाहिए।

पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था हेतु कृषि एवं खाद्य नीति (संयोजक : डॉ. सुरेश पाल)

भारत द्वारा पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि की क्षमता एवं वांछित नीतिगत सुधारों पर चर्चा करने के लिए एक विचार मंथन सत्र का आयोजन किया गया।

विचार मंचन के परिणामस्वरूप उभरी सिफारिशें इस प्रकार थीं:

1. वर्ष 2024—25 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए कृषि विकास को दोगुना करना होगा।
2. सार्वजनिक निवेश, भारतीय कृषि में वृद्धि लाने का एक प्रमुख स्रोत रहा है। अतः निवेश वृद्धि की दर को दोगुना करने की आवश्यकता है। उत्पादकता, स्थिरता एवं बेहतर पर्यावरणीय परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कृषि क्षेत्र में वित्तीय सहायता (सब्सिडी) को फिर से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, पारितंत्रीय सेवाओं के सृजन हेतु कृषि में एक प्रोत्साहन तंत्र



विकसित किया जाना चाहिए। उच्च—मूल्य वाली जिंसों (वस्तुओं) का विविधीकरण खेती और कृषि आय में वृद्धि का मुख्य स्रोत बना रहेगा। इस विविधीकरण के लिए प्रौद्योगिकी, संस्थानों और बाजार के बुनियादी ढांचे को सबल बनाना होगा।

3. कृषि में घरेलू निवेश को आकर्षित करने और कृषि में खेती प्रक्रियाओं के परिचालन के स्तर को बढ़ाने के लिए भूमि सुधार और भूमि—पट्टा बाजार आवश्यक हैं। इसके लिए भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण, मॉडल काश्तकारी अधिनियम को अपनाना तथा संविदा में होने वाले विवादों का निराकरण आवश्यक है। इसी प्रकार, सामान्य और विकृत भूमि की बहाली हेतु उन्हें पट्टे पर देने तथा स्थानीय समुदायों के लिए उपयोगी सेवाओं के सृजन को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
4. वैश्विक बाजार और प्रतिस्पर्धा के आकलन, बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, आपूर्ति शृंखलाओं सहित खाद्य सुरक्षा के लिए अच्छी प्रक्रियाएं तथा आपूर्ति शृंखलाओं के प्रबंधन का पता लगाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक दीर्घकालिक रणनीति बनाई जानी चाहिए।
5. विज्ञान एवं नीति के बीच संबंध (इंटरफेस) को मजबूत बनाया जाना चाहिए और इसलिए साक्ष्य—आधारित नीति तैयार करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
6. व्यापार के अवसर, व्यापार करने में आसानी, जोखिम प्रबंधन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे सङ्क, बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी की एक बड़ी भूमिका होगी इसलिए उन्हें उचित प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
7. केंद्र और राज्यों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और सिंचाई एवं सामुदायिक वनों के सहभागी प्रबंधन की तर्ज पर विकास कार्यक्रमों के स्थानीय शासन में किसानों की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए।

भारत में उच्च कृषि शिक्षा का रूपांतरण (संयोजक: प्रोफेसर आर. बी. सिंह)

नई शिक्षा नीति के साथ कृषि शिक्षा के सामंजस्य हेतु भारत में उच्च कृषि शिक्षा के रूपांतरण पर अकादमी ने एक विचार मंथन सत्र का आयोजन किया।

विचार विमर्श के फलस्वरूप सामने आई सिफारिशें इस प्रकार हैं:

1. राष्ट्रीय कृषि नीति के एक अभिन्न अंग के रूप में कृषि शिक्षा को अपनाया जाए।
2. स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए एक विश्व स्तरीय कृषि विश्वविद्यालय प्रणाली का सृजन किया जाए।
3. एक व्यापक बहु—विषयी शैक्षिक एवं अनुसंधान विश्वविद्यालयों (एमईआरयू) की स्थापना, पारदर्शी शासन, स्वायत्ता, योग्यता, संसाधनों का विवेकपूर्ण आवंटन एवं मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन हेतु जिम्मेदार प्रणालियों को सुनिश्चित कर उन्हें संस्थागत बनाना।

- मानकों, मानदंडों एवं मान्यता पर विशेष ध्यान देते हुए, अंतःप्रजनन (इनब्रीडिंग) को कम करना और संस्थागत संपर्कों को बढ़ाने हेतु कृषि शिक्षा और अनुसंधान में मौलिक एवं उभरते विज्ञान को मजबूत करना और उत्कृष्टता के केंद्रों की देखभाल करना।
- सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करने एवं कृषि में नेतृत्व प्रदान करने हेतु युवाओं को तैयार करने के लिए पाठ्यक्रम, शिक्षण/सीखने की प्रक्रियाओं और शिक्षाशास्त्र में सुधार लाना।
- सक्रिय एवं दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विकास का समर्थन, सफल सहयोग मॉडल का पुनर्गठन एवं पुनरावृत्ति तथा दक्षिण—दक्षिण, दक्षिण—उत्तर और त्रिपक्षीय सहयोग को प्रारंभ करना।
- प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कृषि (व्यापक अर्थ में) शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए।

आलू बीज के उत्पादन में नवोन्मेष ऊंच उनका अनुप्रयोग (संयोजक : डॉ. उस. के. चक्रबर्ती)

डॉ. टी. महापात्र की अध्यक्षता में एक विचार मंथन सत्र का आयोजन किया गया। अपने प्रारंभिक संबोधन में उन्होंने आलू बीज उत्पादन से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डाला।



प्रमुख सिफारिशों निम्नलिखित हैं:

- किसानों को प्रमाणित ग्रेड वाले आलू के बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एपिकल रूटेड कटिंग (एआरसी) जैसी नवीनतम तकनीकों सहित प्रभावी वैकल्पिक बीज उत्पादन मॉडल पर कार्य करना।
- आलू एवं उसके उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाने के लिए वैश्विक स्तर के प्रमाणित आलू बीज के उत्पादन हेतु आवश्यक बुनियादी ढाँचा तैयार करना।

शहरी ऊंच अर्ध-शहरी कृषि में अपशिष्ट जल का उपयोग (संयोजक : डॉ. जे. सी. डागर)

डॉ. टी. महापात्र की अध्यक्षता में एक नीतिगत कार्यशाला का आयोजन किया गया। उन्होंने जल, भोजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की लगातार बढ़ती मांग की चुनौतियों को बताते हुए संकेत दिया कि भविष्य में इनकी मांग और अधिक बढ़ सकती हैं।

विचार विमर्श में निम्नलिखित मुद्दे और सिफारिशों उभर कर सामने आईं:

1. अपशिष्ट जल उपचार के लिए किफायती तथा उपयोगकर्ता एवं पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का विकास करना।
2. ऐसे पानी के सुरक्षित उपयोग के लिए भारी धातुओं के बारे में दिशानिर्देश एवं महत्वपूर्ण सीमाएं विकसित करना।
3. विभिन्न उपयोगों जैसे वानिकी, जलजीव पालन, पशुधन, बागवानी और गैर-खाद्य फसलों में पुनः उपयोग के लिए अपशिष्ट जल का वर्गीकरण करना।
4. जल के विभिन्न गुणों सहित उगाने के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य पौधों की प्रजातियों की पहचान करना।
5. अपशिष्ट जल के प्रभावी उपयोग के कार्यक्रमों से स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम और स्वच्छ भारत जैसी सरकारी योजनाओं को जोड़ना।



भारत में प्रसंस्करण हेतु टमाटर की उपयुक्त किस्मों का प्रजनन (संयोजक : डॉ. उ. टी. सदाशिव)

भारत में टमाटर के प्रसंस्करण की वर्तमान स्थिति और भावी संभावनाओं का आकलन करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

विचार विमर्श के दौरान निम्न प्रमुख सिफारिशें सामने आईं:

1. मशीन द्वारा हार्वेस्टिंग (एमएच) के लिए ठोस फल परिपक्वता (सीएफएम) और जोड़ रहित डंठल सहित उच्च उपजशील, बहु रोग प्रतिरोधी प्रसंस्करण वाली टमाटर की किस्मों और एफ¹ संकर किस्मों को विकसित करने की आवश्यकता है।
2. फार्मास्युटिकल एवं न्यूट्रास्युटिकल उद्योगों के लिए मूल्य वर्धित उत्पादों पर भारतीय टमाटर प्रसंस्करण क्षेत्र को ध्यान देने की आवश्यकता है।
3. टमाटर प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए क्षेत्रों/जिलों की पहचान करना और प्रसंस्करण गुणों सहित विशिष्ट क्षेत्र के लिए टमाटर की किस्मों को विकसित करना।

सीमा-पार संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु भारतीय पशुओं उवं कृककुट के लिए आपातकालीन तैयारियां (संयोजक : डॉ. परिमल राय)

सीमा-पार (ट्रांसबाउंड्री) से आने वाले रोग और उभरती हुई बीमारियाँ पशुधन उत्पादन हेतु गंभीर खतरा हैं। अकादमी ने डॉ. टी. महापात्र की अध्यक्षता में एक विचार मंथन सत्र का आयोजन

किया। अपने प्रारंभिक संबोधन में, उन्होंने नई बीमारियों के प्रकोप के बारे में लोगों को शीघ्रता से सूचित करने, पशु चिकित्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोगजनकता, महामारी विज्ञान, सांख्यिकीय मॉडलिंग, नैदानिकी, जैव सुरक्षा, जीनोमिक्स तथा वैकरीन के विकास से संबंधित मुद्दों की त्वरित जांच और निवारण के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया।

विचार—मंथन सत्र में उभरी प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

1. सीमा—पार पशु रोगों (टीएडी) के निदान के लिए अपेक्षित संगरोध सुविधाओं और बुनियादी ढांचे सहित अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को मजबूत करना।
2. एक सक्रिय राष्ट्रीय रोग निगरानी तंत्र का विकास।
3. टीएडी के नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग हेतु सहमति बनाना।
4. आपातकालीन तैयारियों के लिए एसओपी एवं दिशा—निर्देशों में सामंजस्य बिठाना।



कृषि के स्वपांतरण हेतु संविदा खेती : चुनौतियां तुवं भावी मार्ग (संयोजक : डॉ. अंजनी कुमार)

नए कृषि अधिनियम में संविदा खेती पर चर्चा के लिए एक विचार मंथन सत्र का आयोजन किया गया। नया संविदा कृषि अधिनियम, संविदाओं को आगे बढ़ाने में स्वयं सक्षम नहीं हो सकता है। यह अधिनियम एफपीओ को व्यापार में शामिल होने और कॉर्पोरेट खरीदारों और फर्मों के साथ अनुबंध करने के व्यापक अवसर प्रदान करता है लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए कुछ अन्य कदम उठाने की भी जरूरत है। संविदा खेती को सुविधाजनक बनाने के लिए, कुछ संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है।

इसमें सुझाई गई कुछ रणनीतियाँ इस प्रकार हैं:

1. बुनियादी ढांचे के उन्नयन एवं व्यवस्था में सुधार लाकर एपीएमसी प्रणाली को मजबूत करके प्रतिस्पर्धा और बेहतर मूल्य को सुनिश्चित करना। किसानों की होलिंग कैपेसिटी (धारण क्षमता) में सुधार, सौदेबाजी क्षमता में सुधार और इस प्रकार बेहतर मूल्य प्राप्ति द्वारा ग्राम या समुदाय

(क्लस्टर) स्तर पर विकेन्द्रीकृत भंडारण, गुणवत्ता नियंत्रण, बुनियादी ढांचे और कम पूँजी युक्त प्रसंस्करण सुविधाओं का निर्माण करना।

2. बाजार की जानकारी में विषमता के कुछ मुद्दों को ठीक करने के लिए बाजार आसूचना प्रणाली और साधनों को विकसित करना।
3. कई बाजार श्रृंखलाओं (मार्केटिंग चौनलों) एवं स्थानों के चयन में छोटे किसानों को सक्षम बनाने के लिए वित्तीय समावेशन में सुधार महत्वपूर्ण है।

जैवखेती हेतु पराजीनी कुककुट पालन की संभावनाएं (संयोजक : डॉ. टी. के. श्रद्धाचार्य)

डॉ. टी. महापात्र की अध्यक्षता में एक नीतिगत कार्यशाला का आयोजन किया गया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए बायोफार्मिंग आज के समय की आवश्यकता है। जरूरतमंद लोगों के इलाज के लिए फार्मास्यूटिकल्स की उत्पादन लागत को कम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि परंपरागत सेल लाइन—आधारित प्रणाली की तुलना में जिसकी उत्पादन क्षमता सीमित है, पराजीनी पशुओं एवं कुककुट पालन के उपयोग से बड़ी मात्रा में चिकित्सीय उत्पादन को संभव बनाया जा सकता है।



विचार विमर्श के पश्चात निम्नलिखित सिफारिशों सामने आईः

1. बायोसिमिलर, इम्युनोग्लोबुलिन एवं साइटोकिन्स सहित बॉयोफार्मास्यूटिकल्स के उत्पादन के लिए ट्रांसजेनिक पोल्ट्री प्लेटफॉर्म को प्राथमिकता दी जाए।
2. वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं एवं अन्य स्टेकहोल्डरों में ट्रांसजेनिक पशुओं से सस्ती कीमतों पर चिकित्सा संबंधी उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों को अपनाने के प्रति जागरूकता पैदा की जाए।
3. पराजीनी (ट्रांसजेनिक) पशुओं के विकास हेतु डीबीटी (आरसीजीएम) तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (जीईएसी) द्वारा तैयार जैव सुरक्षा दिशानिर्देशों को ट्रांसजेनिक पशुओं के विकास के लिए सरल बनाने की आवश्यकता है।
4. ट्रांसजेनिक पशु अनुसंधान के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा सृजित किए जाने की आवश्यकता है, और किफायती चिकित्सा प्रणाली (थेराप्यूटिक्स) के लिए ट्रांसजेनिक पशु प्लेटफॉर्म विकसित करने में सहयोग की आवश्यकता है।

अदृश्य भूख के निदान हेतु जैवसंपूरण (बायोफोर्टिफिकेशन) पर विचार विमर्श (संयोजक: डॉ. यू. उस. सिंह)

जैवसंपूरण (बायोफोर्टिफिकेशन) वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा फसलीय प्रक्रियाओं, पारंपरिक पादप प्रजनन, या आधुनिक जैव-प्रौद्योगिकी के माध्यम से खाद्य फसलों की पोषण गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। बायोफोर्टिफिकेशन का उद्देश्य पौधों की वृद्धि के दौरान फसलों में पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाना है। इसलिए, बड़ी संख्या में ग्रामीण निर्धनों तक पहुंचने के लिए मुख्य फसलों का जैवसंपूरण एक प्रभावी विकल्प है। स्थायी आधार पर बड़ी संख्या में गरीबों तक पहुंचने के लिए यह एक किफायती विधि है।

26 मार्च, 2021 को अकादमी द्वारा “अदृश्य भूख एवं पोषण सुरक्षा को संबोधित करने के लिए जैवसंपूरण : वर्तमान स्थिति एवं भावी मार्ग” पर एक नीतिगत संवाद का आयोजन किया गया था। इस सत्र की अध्यक्षता नास के अध्यक्ष डॉ. टी. महापात्र और सह-अध्यक्षता डॉ. हृगो कैम्पोस, निदेशक अनुसंधान, सीआईपी, लीमा, पेरू ने की। इस सत्र में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने सहभागिता की। दो सत्रों में नीतिगत संवाद की योजना बनाई गई थी। पहले सत्र में प्रमुख फसलों की वर्तमान स्थिति और जैवसंपूरण की भावी दिशा पर चर्चा की गई। इसमें शामिल फसलों में शकरकंद, आलू, चावल, गेहूं बाजरा, दलहन और किवनोआ थीं। रासायनिक साधनों के माध्यम से दो महत्वपूर्ण प्रमुख फसलों चावल एवं गेहूं के जैव-संपूरण पर भी प्रकाश डाला गया। पश्च उत्पादों के जैवसंपूरण के दायरे पर विशेष प्रस्तुति दी गई। दूसरे सत्र में अदृश्य भूख की समस्या को हल करने और बायोफोर्टिफाइड उत्पादों को बढ़ाने के लिए आवश्यक रणनीतियों और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतियों के संदर्भ में पोषण सुरक्षा को संबोधित करने पर केंद्रित किया गया।

‘अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर चर्चा : कृषि विज्ञान में महिलाओं की भूमिका’ पर पैनल चर्चा (संयोजक : प्रोफेसर के. सी. बंसल)

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी ने 8 मार्च, 2021 को अपने अध्यक्ष डॉ. त्रिलोचन महापात्र की अध्यक्षता में ‘कृषि विज्ञान में महिलाओं की भूमिका’ पर एक वर्चुअल पैनल चर्चा का आयोजन करके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, इस सत्र की सह-अध्यक्षता अकादमी के उपाध्यक्ष डॉ. जे. सी. कत्याल ने की।

अपने प्रारंभिक संबोधन में डॉ. टी. महापात्र ने उल्लेख किया कि अकादमी पहली बार महिला दिवस मना रही है। महिला वैज्ञानिक लीडरों को व्यक्तिगत सम्मान देते हुए, उन्होंने महिलाओं के योगदान को सम्मान देने एवं उन्हें मान्यता देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कृषि सहित प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की कार्य कुशलता की सराहना की। कृषि में महिला वैज्ञानिक और महिला कामगार राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कृषि में महिलाओं के लिए एक अलग संस्थान बनाने के लिए भाकृअनुप के दृष्टिकोण की सराहना की जो दुनिया में अपनी तरह का एक विशिष्ट संस्थान है।

तथापि, उन्होंने भाकृअनुप प्रणाली में महिला वैज्ञानिकों की कम संख्या पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश में संस्थापित विभिन्न विज्ञान अकादमियों में, नास में महिला अध्येताओं (फैलो) का अनुपात केवल 6.5% है जबकि आईएनएसए में 9%, आईएएससी में 8.9% एवं एनएएसआई में 12% है। उन्होंने छात्राओं को उनके स्कूल में प्रवेश के बाद से ही नेतृत्व हेतु तैयार करने के लिए सलाह देने में अकादमी की भूमिका को दोहराया। उन्होंने यह भी बताया कि बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस बंधन को तोड़ा है और विज्ञान के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान एवं सक्षम नेतृत्व प्रदान किया है।

इक्रिसेट (आईसीआरआईएसएटी), हैदराबाद की महानिदेशक डॉ. जैकलीन डी' एरोस ह्यूजेस ने इस कार्यक्रम में अपना प्रमुख व्याख्यान (की नोट लेकचर) प्रस्तुत किया। उन्होंने इस दिन को महिलाओं के लिए अवकाश घोषित करने के तेलंगाना सरकार द्वारा उठाए गए कदम की सराहना की। उन्होंने कहा 'मैं कभी भी महिला समर्थक या लिंग समर्थक नहीं रही हूं। मैं सर्वश्रेष्ठ के पक्ष में हूं और मेरा मानना है कि हमें महिलाओं को अतिरिक्त समर्थन देने की जरूरत है।' उन्होंने विशेषकर भारत के संदर्भ में उत्पादकता, समानता और समृद्धि पर जोर दिया और अनुसंधान और खेत दोनों में उत्पादकता एवं उत्पादन को बढ़ाने में महिलाओं की भूमिका की चर्चा की।

डॉ. रूपमंजरी घोष, कुलपति, शिव नादर विश्वविद्यालय, नोएडा ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट होता है और वह हमारे समाज के निर्माण में भी अद्वितीय होता है, इसलिए हमें उस विशिष्टता का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह पुरुष हो या महिला। उच्च शिक्षा प्रणाली में, हमें विवेकयुक्त तरीके से इस अंतर को समझने की जरूरत है। इस तथ्य से आश्वस्त होते हुए कि प्रत्येक महिला अंदर से एक विशेष गुण सम्पन्न महिला है, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एक संस्थान में लिंग पूर्वाग्रह के प्रति शून्य सहिष्णुता होनी चाहिए।

"कृषि विज्ञान में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना" विषय पर पैनल चर्चा की सह-अध्यक्षता डॉ. जे. सी. कात्याल एवं डॉ. ए. के. सिंह. ने की। नेचर इंडिया की मुख्य संपादक सुश्री शुभ्रा प्रियदर्शिनी ने इस प्रतिष्ठित पत्रिका का विवरण दिया। उन्होंने विज्ञान में संचार के महत्व पर जोर दिया तथा इसमें महिलाओं को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। विज्ञान संचार का महत्व विज्ञान से संबंधित विषयों के बारे में जानकारी देने, शिक्षित करने, जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ वैज्ञानिक खोजों और तर्कों के बारे में जिज्ञासा की भावना को बढ़ाने और इस प्रकार व्यक्तियों, विशेष रूप से युवाओं को विज्ञान के बारे में प्रेरित करना है। भाकृअनुप-राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, त्रिची की निदेशक डॉ. एस. उमा ने राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) में महिलाओं के शीर्षस्थ पदों पर होने के कई उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि कृषि अनुसंधान में महिलाओं को अपने पुरुष सहकर्मियों की तुलना में अपनी विशेषज्ञता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है और इसके लिए उन्हें पुरजोर पारिवारिक समर्थन की भी आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि प्रणाली द्वारा महिला वैज्ञानिकों को उपयुक्त रूप से पहचान/मान्यता देने हेतु और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। डॉ. सुनीता ग्रोवर, पूर्व प्रभागाध्यक्ष, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, एनडीआरआई, करनाल ने कृषि में महिलाओं की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि

कृषि में महिलाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं जो इस बात से स्पष्ट है कि अब तक लगभग 60 महिलाओं ने प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। उन्होंने प्रसिद्ध विज्ञानुविद् (वायरोलॉजिस्ट) डॉ. गगनदीप कांग का उदाहरण दिया जो रॉयल सोसाइटी की फैलोशिप प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है।

अकादमी के सचिव डॉ. पी. के. जोशी ने कृषि विकास में महिला वैज्ञानिकों की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रणाली (नास) में 'महिला वैज्ञानिकों का कार्यबल' गठित करने का सुझाव दिया। यह कार्यबल एक पोजिशन पेपर (यथास्थिति पत्र) तैयार कर सकता है।

पैनल चर्चा में निम्नलिखित बिंदु सामने आए:

1. महिलाओं में विशिष्टता की पहचान हेतु एक नवोन्मेषी एवं पारदर्शी प्रणाली की आवश्यकता है।
2. कृषि शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं के बढ़ते अनुपात के बावजूद कृषि अनुसंधान प्रणाली (एआरएस) में 4% वैज्ञानिकों में से केवल 2% ही महिलाएं हैं और इनमें से भी मुश्किल से 1% ही नेतृत्व के शिखर तक पहुँच पाती हैं। सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली में महिला आरक्षण लागू करने लेकिन सरकारी सेवाओं में उसे लागू न करने के कारण नौकरी में महिला प्रोफेशनलों का अनुपात कम हो सकता है। हालांकि, कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण लाने से इस स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।
3. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह की तरह नास भी राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना शुरू कर सकता है।
4. भारतीय समाज ने हमेशा ही महिलाओं को सम्मान दिया है, लेकिन बेहतर पेशेवरों की पहचान करना भी चाहित है।
5. डॉ. जे. सी. कत्याल ने अपने समापन भाषण में कहा कि भाकृअनुप ने युवा महिला वैज्ञानिक पुरस्कार का गठन किया है। उन्होंने कहा कि यह भी सच है कि चिकित्सा, आईसीटी और अन्य विज्ञानों की तुलना में महिलाएं कृषि विज्ञान में कम रुचि दिखाती हैं, इसलिए हमें उन्हें प्रेरित करने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने महिलाओं को एआरएस प्रणाली में सम्मिलित करने की नीति पर एक विचार-मंथन सत्र के आयोजन की सिफारिश की।

15वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस - ऊर्जा उत्तर कृषि: 21वीं सदी में चुनौतियां

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी के सहयोग से नास (नास) द्वारा ऊर्जा एवं कृषि: 21वीं सदी में चुनौतियां पर 13–16 नवंबर, 2021 के दौरान बीएचयू वाराणसी में 15वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस (एएससी) का आयोजन किया जाएगा। इस चार दिवसीय कार्यक्रम में तकनीकी सत्र, पूर्ण सत्र, सार्वजनिक व्याख्यान, किसान सत्र, पोस्टर प्रस्तुतीकरण, अंतर-विश्वविद्यालय छात्र संभाषण प्रतियोगिता, पैनल चर्चा और कई सेटेलाइट बैठकों का आयोजन किया जाएगा। एएससी-एग्रिटैक-2021 इस कांग्रेस का एक प्रमुख संबद्ध कार्यक्रम होगा। अकादमी द्वारा आयोजित इस द्विवार्षिक सम्मेलन में विभिन्न

विषयों के शोधकर्ताओं, शिक्षकों, नीति निर्माताओं, किसानों, उद्यमियों, विकास विभागों, कॉर्पोरेट और निजी क्षेत्र के नेताओं, गैर सरकारी संगठनों और छात्रों के बड़ी संख्या में भाग लेने की उम्मीद है।

क्षेत्रीय चैप्टर

कृषि से संबंधित राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों को संबोधित करने के लिए क्षेत्रीय चैप्टरों (केंद्रों) द्वारा निम्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम	दिनांक एवं स्थान
बारापानी चैप्टर	
कृषि महाविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल, किर्डमकुलाई, के सहयोग से रिमोई जिला, मेघालय में 'ग्रामीण जैव-उद्यमिता हेतु समेकित कृषि' पर विचार मंथन सत्र का आयोजन	8 फरवरी, 2021 नोंगस्टोइन कॉलेज, नोंगस्टोइन, पश्चिमी खासी पर्वतीय जिला, मेघालय
'समेकित कृषि के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत ' पर विचारमंथन –सह– कार्यशाला	9 मार्च, 2021 सीएयू इम्फाल
बैंगलुरु चैप्टर	
डॉ. श्रीनि वी. कावेरी, निदेशक, भारतीय सीएनआरएस कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा 'पर्यावरण एवं हमारा प्रतिरक्षा तंत्र : महामारी ने हमें क्या सिखाया?' पर एक वार्ता का प्रस्तुतीकरण	26 फरवरी, 2021
डॉ. कालिदास शेट्टी, इंटरनेशनल पार्टनरशिप एंड कॉलेबोरेशन के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट तथा ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल एग्रिकल्चर, नार्थ डेकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी, यूएसए के संस्थापक निदेशक द्वारा "पोस्ट-कोविड-19: लेसन एंड स्ट्रैटेजीज फॉर एडवांसिंग ग्लोबल फूड सिस्टम फॉर क्लाइमेट-रेसिलिएंट फूड सिक्योरिटी एंड हेल्थ" पर एक व्याख्यान दिया गया।	27 मार्च, 2021
भोपाल चैप्टर	
भाकृअनुप-भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान के सहयोग से भोपाल चैप्टर द्वारा डॉ. रतन लाल, वर्ल्ड फूड प्राइज, 2020 लॉरेट को सम्मानित किया गया।	21 जुलाई, 2020

कार्यक्रम	दिनांक एवं स्थान
भाकृअनुप—भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान के सहयोग से भोपाल चैप्टर द्वारा 'कृषि में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की संभावना ' पर एक वेबनार का आयोजन किया गया।	28 फरवरी, 2021
कोयम्बटूर चैप्टर	
इंडियन सोसायटी ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, नई दिल्ली एवं भाकृअनुप — एसबीआई, कोयम्बटूर के सहयोग से 'फसलीय पौधों में जैविक एवं अजैविक तनाव पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव' पर विचार—मंथन सत्र का आयोजन किया गया।	11 मार्च, 2021
कटक चैप्टर	
सीआआरआई हाईस्कूल, कटक के छात्रों के लिए कोविड-19 महामारी पर सामान्य जागरूकता विवरण का ऑनलाइन आयोजन किया गया।	18–19 सितंबर, 2020
हैदराबाद चैप्टर	
हैदराबाद चैप्टर के अध्येताओं (फैलो) एवं सहयोगियों ने श्री गोविंदा राजुलु चिंटाला, चैयरमैन, नाबार्ड के साथ एक वर्चुअल विचार विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया।	भाकृअनुप—नार्म, 27 अगस्त, 2020
संकल्प 2020: राष्ट्रीय व्यापार महोत्सव। भाकृअनुप — राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, हैदराबाद के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एग्रीबिजनेस मैनेजमेंट (पीजीडी—एबीएम) के छात्रों द्वारा नास — हैदराबाद चैप्टर, समुनाती फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा रैलिस इंडिया लिमिटेड, सेव फाउंडेशन तथा नार्म के ए—आइडिया (एग्री—बिजनेस इनक्यूबेटर) के सहयोग से दो दिवसीय राष्ट्रीय बिजनेस—फेस्ट (संकल्प—2020) का आयोजन किया गया।	4–5 अक्टूबर, 2020
भाकृअनुप—राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र तथा भाकृअनुप — राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी के सहयोग से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के राज्य कृषि/पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए "भारत में मानव स्वास्थ्य हेतु बेहतर पोषण और प्रभाव के लिए संतुलित पशु प्रोटीन का उपभोग" पर एक वैज्ञानिक निबंध—लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।	नवंबर, 2020

कार्यक्रम	दिनांक एवं स्थान
भाकृअनुप—राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी (नार्म), हैदराबाद द्वारा संयुक्त रूप से नास – हैदराबाद चैप्टर, इंडियन मीट साइंस एसोसिएशन (आईएमएसए), और मांस पर भाकृअनुप—एनआरसी द्वारा 'भैंस मांस क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु वैज्ञानिक हस्तक्षेप एवं नीतियां : भारत की कृषि—अर्थव्यवस्था के उन्नयन हेतु उत्प्रेरक' पर एक शिक्षाविदों – सरकारी परामर्शी कार्यशाला का आयोजन किया गया।	19 जनवरी, 2021
भाकृअनुप—राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी तथा पीवी नरसिंहा राव तेलंगाना राज्य पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से "उद्यमिता एवं संचार कौशल विकास" पर पांच दिवसीय छात्र मार्गदर्शी (मेंटरिंग) प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।	12 मार्च, 2021 पशुचिकित्सा महाविद्यालय, हैदराबाद
भाकृअनुप – नार्म, हैदराबाद ने आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय तथा नास, हैदराबाद चैप्टर के सहयोग से कृषि महाविद्यालय, महानंदी के छात्रों के लिए "कृषि एवं सबद्ध क्षेत्रों में सक्षमता उन्नयन एवं छात्र परामर्श" पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।	5–6 मार्च, 2021 कृषि महाविद्यालय, महानंदी
आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से कृषि महाविद्यालय, राजमहेंद्रवरम के छात्रों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।	9–10 मार्च, 2021
करनाल चैप्टर	
डॉ. एम. एल. मदान की अध्यक्षता में नास के फैलो (अध्येताओं) एवं सहयोगियों की एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें पिछले वर्ष की गतिविधियों की समीक्षा की गई तथा 2021 की योजना तैयार की गई।	28 जनवरी, 2021
कोलकाता चैप्टर	
सोसाइटी फॉर फर्टिलाइजर्स एंड एनवायरनमेंट के साथ संयुक्त रूप से "जैव विविधता एवं मृदा के कार्यों" पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया।	5 दिसंबर, 2020

कार्यक्रम	दिनांक एवं स्थान
लखनऊ चैप्टर	
राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (नास) के दो महत्वपूर्ण प्रकाशनों (नीति पत्र 90 एवं 91) का हिंदी में अनुवाद करके उन्हें प्रकाशित किया गया।	
भाकृअनुप – सीएसएसआरआई करनाल क्षेत्रीय स्टेशन, लखनऊ के सहयोग से “संसाधन विहीन किसानों की आजीविका सुरक्षा के लिए जल भराव वाली क्षारीय मृदा के प्रबंधन” पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया।	13 अक्टूबर, 2020
लुधियाना चैप्टर	
पीएयू लुधियाना के सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 तथा कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान पर ऑनलाइन पैनल चर्चा का आयोजन किया गया।	16 सितंबर, 2020
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र, रोपड़ ने लुधियाना चैप्टर के सहयोग से ‘फसल अवशेष प्रबंधन’ पर एक वेबिनार का आयोजन किया।	29 सितंबर, 2020
डॉ. अतुल, पूर्व निदेशक, विस्तार शिक्षा, सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय (एचपीकेवी), पालमपुर द्वारा “आज की डिजिटल दुनिया में संचार के आधुनिक उपकरण एवं तकनीकों” पर एक ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया गया।	1 अक्टूबर, 2020
बुध सिंह वाला, मोगा में पीएयू के कृषि विज्ञान केंद्र ने लुधियाना चैप्टर के तत्वावधान में ‘कृषि अपशिष्ट/पराली जलाने के खतरे को रोकने में स्कूल/कॉलेज के छात्रों की भूमिका’ पर एक वेबिनार का आयोजन किया।	13 अक्टूबर, 2020
लुधियाना चैप्टर द्वारा होशियारपुर जिले में स्कूली छात्रों के माध्यम से फसल अवशेष प्रबंधन अभियान चलाया गया।	7 दिसंबर, 2020
पुणे चैप्टर	
भाकृअनुप – राष्ट्रीय अजैविक तनाव प्रबंधन संस्थान (एनआईएसएम) तथा कृषि विज्ञान में अजैविक तनाव अनुसंधान सोसायटी (एसएआरएएस) के साथ संयुक्त रूप से “महाराष्ट्र कृषि में अजैविक तनाव प्रबंधन” पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया।	20 फरवरी, 2021

कार्यक्रम	दिनांक एवं स्थान
वाराणसी चैप्टर	
माइक्रोटेक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, वाराणसी के बी.एससी. (कृषि) के छात्रों हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी की भूमिकाओं एवं गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया गया।	31 अगस्त, 2020
वैज्ञानिक खेती प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए अनुसूचित जाति के किसानों के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।	19 नवंबर, 2020 को मिर्जापुर जिले का नरायनपुर ब्लॉक
11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान एवं कृषि के 150 से अधिक छात्रों के लिए कृषि एवं संबद्ध विज्ञान में जीविका-वृत्ति के अवसरों पर एक विज्ञान जागरूकता अभियान चलाया गया।	22 दिसंबर, 2020 राजकीय इंटर कॉलेज, जिंठिनी, वाराणसी

वर्ष 2020-21 के दौरान क्षेत्रीय चैप्टरों की गतिविधियां

कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न गंभीर स्थिति के बावजूद, नास के क्षेत्रीय केंद्रों ने क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने हेतु वैज्ञानिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय प्रयास किए। कुछ को छोड़कर, अधिकांश गतिविधियां वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित की गईं।

बारापानी चैप्टर ने कृषि महाविद्यालय, (केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंफाल, मेघालय) के सहयोग से “ग्रामीण जैव-उद्यमशीलता हेतु एकीकृत कृषि” पर एक विचार-मंथन सत्र और “एकीकृत कृषि के माध्यम से आत्म निर्भर भारत” पर एक विचार-मंथन-सह-कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें कई कृषि वैज्ञानिकों और सरकारी विभागों के अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं ने सहभागिता की। कृषि-व्यवसाय के अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करने और स्थानीय लोगों के बीच नए तकनीकी नवोन्मेषों के बारे में जानकारी देने जैसी गतिविधियों की अत्यधिक सराहना की गई।

बंगलुरु चैप्टर ने डॉ. श्रीनि वी. कावेरी, निदेशक, सीएनआरएस ऑफिस इन इंडिया, नई दिल्ली द्वारा “पर्यावरण और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली: महामारी ने हमें क्या सिखाया है?” पर एक अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया। इसमें 90 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें भारतीय लोगों की जीवनशैली एवं विशिष्ट आहार की आदतों पर प्रकाश डाला गया जिसमें रोजमर्रा के भोजन में सम्मिलित लाभकारी मसाले शामिल हैं (जो भारतीयों की बेहतर प्रतिरक्षा में योगदान दे सकते हैं)। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय लोगों की व्यापक आनुवंशिक विविधता का बेहतर प्रतिरक्षा में क्या योगदान है, इस पर विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता है।

बैंगलुरु चैप्टर ने ही डॉ. कालिदास शेष्टी, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट फॉर इंटरनेशनल पार्टनरशिप एंड कॉलैबोरेशन तथा ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्वर, नॉर्थ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी, यूएसए के संस्थापक निदेशक ने 'जलवायु के प्रति लचीली खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य हेतु वैश्विक खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए पोस्ट-कोविड-19 से सीख एवं रणनीतियाँ' विषय पर एक अन्य व्याख्यान आयोजित किया। उन्होंने पारंपरिक भोजन की आदतों के लाभों पर जोर दिया और आहार से सम्बद्ध पुरानी बीमारियों के निदान हेतु ज्ञात स्वास्थ्य लाभों के साथ पारंपरिक फसलों की फिर से खेती करने की सिफारिश की।

भोपाल चैप्टर ने भाकृअनुप – भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान के साथ संयुक्त रूप से आयोजित एक वर्चुअल समारोह में 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता डॉ. रतन लाल को सम्मानित किया। भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉ. रतन लाल ने खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए मृदा पर आधारित दृष्टिकोण विकसित करने और उसे मुख्यधारा में सम्मिलित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है जिससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के तीन अलग-अलग सम्मेलनों ने कार्बन को अलग करने तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने के एक साधन के रूप में मृदा स्वास्थ्य को पुनःस्थापित करने की उनकी रणनीति को अपनाया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. एस. के. चौधरी, उप महानिदेशक (एनआरएम), भाकृअनुप ने की। अपने संबोधन में डॉ. रतन लाल ने मृदा द्वास पर अनुसंधान को मजबूत करने का प्रस्ताव रखा, जिसके कारण भारत में अन्य देशों की तुलना में कई फसलों की कम उपज प्राप्त होती है। उन्होंने आगाह किया कि निवेश (इनपुट) आधारित कृषि पर अधिक जोर देने से फसल की पैदावार कम होती है और इसके अलावा कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं तथा मृदा के स्वास्थ्य में और अधिक गिरावट आती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोविड -19 संकट से निपटने हेतु 'वन हैल्थ स्ट्रेटेजी' (एक स्वास्थ्य रणनीति) को क्रियान्वित करने की जरूरत है।

28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर भोपाल चैप्टर एवं भाकृअनुप – भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल ने संयुक्त रूप से कृषि में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की संभावनाएं विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इसमें टिकाऊ कृषि में प्राकृतिक संसाधनों की भूमिका, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में मृदा और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में आने वाली समस्याओं को दूर करने तथा सस्योपरांत होने वाले नुकसान को कम करने में एआई एवं शीतलन प्रौद्योगिकियों (कूलिंग टैक्नोलॉजी) जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।



कोयंबटूर चैप्टर द्वारा इंडियन सोसाइटी ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, नई दिल्ली एवं भाकृअनुप – एसबीआई, कोयंबटूर के सहयोग से भाकृअनुप – एसबीआई में फसलीय पौधों में अजैविक एवं जैविक

तनाव पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर एक विचार—मंथन सत्र का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर एस. आर. श्री रंगास्वामी, एफनास ने की। नास के फैलो (अध्येताओं) सहित लगभग 25 प्रतिभागियों ने व्यक्तिगत रूप से इस कार्यक्रम में सहभागिता की तथा 114 लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया।

इसमें निम्नलिखित प्रमुख अनुशंसाएं की गईः

1. विभिन्न फसलों पर जलवायु का अलग—अलग प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इसलिए विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विभिन्न फसल प्रणालियों में जलवायु परिवर्तन का समग्र रूप से (होलिस्टिक) अध्ययन करने की आवश्यकता है।
2. अजैविक तनाव से महामारियों की गंभीरता बहुत अधिक प्रभावित होती है। इसलिए, रोगाणुओं की नए रूपों (रेसेज) के विकास पर जलवायु कारकों में परिवर्तन की सीमा, कीटों के जैवरूप, कीटों के लक्षणसमष्टि (फेनोटाइप) में अनुकूली परिवर्तन, नए कीटों एवं रोगों के आक्रमण आदि की विस्तृत जांच की आवश्यकता है।
3. पोषक — रोगाणु के बीच अंतःक्रियाओं की आण्विक पारिस्थितिकी को समझने के लिए पोषक —रोगाणु अंतःक्रियाओं में बदलाव हेतु जीन की अभिव्यक्ति पर जलवायु के प्रभाव को नए सिरे से स्पष्ट करने की आवश्यकता है।



राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के कटक चैप्टर द्वारा 18–19 सितंबर, 2020 को सीआरआरआई हाई स्कूल, कटक के छात्रों के लिए कोरोना महामारी की गंभीरता को नियंत्रित करने के इसके कारणों, प्रभावों और कुछ उपचारात्मक उपायों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन कोविड –19 महामारी सामान्य जागरूकता प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

हैदराबाद चैप्टर ने भावी गतिविधियों की समीक्षा एवं योजना बनाने के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित नास फेलो एवं एसोसिएट्स की एक वर्चुअल बैठक के अलावा अन्य कई गतिविधियों का



संचालन किया। इस बैठक में तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के 30 फैलो (अध्येताओं) और एसोसिएट्स ने भाग लिया। नास के अध्यक्ष डॉ. टी. महापात्र, एवं उपाध्यक्ष डॉ. ए. के. सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे। डॉ. त्रिलोचन महापात्र द्वारा नास के हैदराबाद चैप्टर की इंवेटरी (सूची) पर एक प्रकाशन भी जारी किया गया।

श्री गोविंदा राजुलु चिंताला, अध्यक्ष, नाबार्ड ने 27 अगस्त, 2020 को भाकृअनुप—नार्म में **हैदराबाद चैप्टर** के अध्येताओं एवं एसोसियेट के साथ वर्चुअल विचार विमर्श किया। उन्होंने कृषि विकास पर नाबार्ड के विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया तथा अनुसंधान, शिक्षा एवं विस्तार के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री के आह्वान को साकार करने के लिए कृषि—उद्यमिता की पुरजोर सिफारिश की।

भाकृअनुप – राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और प्रबंधन अकादमी (नार्म), हैदराबाद द्वारा 19 जनवरी, 2021 को हैदराबाद चैप्टर, इंडियन मीट साइंस एसोसिएशन (आईएमएसए) तथा भाकृअनुप— एनआरसी ऑन मीट के साथ संयुक्त रूप से ‘भैंस मांस क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए वैज्ञानिक हस्तक्षेप एवं नीतियां: भारत की कृषि—अर्थव्यवस्था को बढ़ाने हेतु उत्प्रेरक’ विषय पर शिक्षाविदों – सरकारी परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस विमर्श में उभरी प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :

1. भैंस के बछड़ों में कम उम्र में मृत्यु दर को रोकने और उनकी वृद्धि के साथ—साथ किफायती दुर्घट प्रतिस्थापक एवं बछड़ा स्टार्टर्स को बढ़ावा देने पर अध्ययन की आवश्यकता है।
2. पशुओं के दैनिक शारीरिक भार में वृद्धि एवं शव (करकास) से उपयोगी पदार्थ की प्राप्ति में सुधार हेतु मांसपेशियों की वृद्धि और उत्पादन प्रणालियों में संभावित सुधार को समझने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता है।

3. मांस उत्पादों में रासायनिक अवशेषों की निगरानी तथा उच्च मूल्य वाले उप-उत्पादों का विकास।
4. भैंसों की उम्र निर्धारित करने के लिए डीएनए-प्रोटीन आधारित विधियों का विकास।
5. विभिन्न परिस्थितियों में भैंस उत्पादन के लिए कृषि प्रणाली मॉडल विकसित करने की आवश्यकता है। वास्तविक समय पर भैंस के बछड़ा पालन के ऑन-फार्म अर्थशास्त्र को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है।
6. विश्वविद्यालयों एवं भाकृअनुप संस्थानों को उत्पादकों, संसाधकों, खुदरा विक्रेताओं, कसाइयों के लिए स्वच्छ मांस उत्पादन एवं मूल्य संवर्धन पर प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने तथा खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं आहार जोखियों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है।
7. पशु संरक्षण अधिनियमों में संशोधन की आवश्यकता है। मांस उत्पादन के लिए भैंस के बछड़े की सुरक्षा एवं उन्हें पालने को बढ़ावा देने की जरूरत है।
8. किसानों की आय में वृद्धि हेतु विभिन्न प्रजातियों के लिए पशुधन बाजार विकसित करने की आवश्यकता है।
9. मांस और दुग्ध उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भैंस की अधिक आबादी वाले समृद्ध राज्यों जैसे— उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश में एफएमडी मुक्त क्षेत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।



कृषि महाविद्यालय, महानंदी के छात्रों को कृषि में आजीविका वृत्ति (करियर) के अवसरों, कृषि शिक्षा, कृषि-उद्यमिता एवं कृषि से संबद्ध अन्य क्षेत्रों में संभावनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए भाकृअनुप – नार्म एवं आचार्य एन. जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से 'कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सक्षमता में वृद्धि एवं छात्र परामर्श' पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

करनाल चैप्टर ने पिछली तिमाही के दौरान आयोजित कार्यक्रमों और 2021 में प्रस्तावित गतिविधियों की समीक्षा के लिए डॉ. एम. एल. मदान की अध्यक्षता में नास फेलो एवं एसोसिएट्स की एक बैठक आयोजित की।

कोलकाता चैप्टर ने 5 दिसंबर को सोसाइटी फॉर फर्टिलाइजर्स एंड एनवायरनमेंट के साथ मिलकर विश्व मृदा दिवस मनाया और एक वेबिनार का आयोजन किया। इस वर्ष के मृदा दिवस की थीम – “मृदा को जीवंत बनाएं – मृदा जैव विविधता की रक्षा करें” को ध्यान में रखते हुए डॉ. टी. के. आध्या, प्रोफेसर, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, केआईआईटी, भुवनेश्वर ने ‘बदलते परिदृश्य में जैव विविधता और मृदा के कार्यों’ पर एक व्याख्यान दिया।

लखनऊ चैप्टर द्वारा नास (पॉलिसी पेपर 90 एवं 91) के दो महत्वपूर्ण प्रकाशनों के व्यापक प्रसार एवं प्रभावी कार्यान्वयन हेतु हिंदी में अनुवाद किया गया।

भाकृअनुप –सीएसएसआरआई क्षेत्रीय स्टेशन के सहयोग से लखनऊ चैप्टर ने ‘संसाधन विहीन किसानों की आजीविका सुरक्षा के लिए जलभराव वाली क्षारीय मृदा के प्रबंधन’ पर एक वेबिनार का आयोजन किया जिसमें मृदा एवं जल की उत्पादकता में सुधार के लिए उठी हुई क्यारियों एवं तालाब (1:1 अनुपात) वाली भूमि संशोधन मॉडल (एलएमएम) द्वारा जलभराव वाली क्षारीय मृदा के प्रबंधन हेतु एक नई विधि पर प्रकाश डाला गया।

नास के लुधियाना चैप्टर ने ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 तथा कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान’ पर एक ऑनलाइन पैनल चर्चा का आयोजन किया। इसमें उभरी प्रमुख टिप्पणियां इस प्रकार थीं :

कृषि विश्वविद्यालयों (एयू) की तुलना पारंपरिक विश्वविद्यालयों से नहीं की जा सकती क्योंकि इनका अधिदेश अलग होता है। यह मानते हुए कि आधे से अधिक बजट शोध कार्य पर खर्च किया जाता है, कृषि विश्वविद्यालय (एयू) अनुसंधान के रूप भी शैक्षणिक संस्थानों जैसे हैं, क्योंकि इनमें बहु विषयी पारंपरिक विश्वविद्यालयों की तुलना में अनुसंधान पर व्यापक रूप से ध्यान दिया जाता है।



कृषि अनुसंधान में हमेशा उतने शोधपत्र प्रकाशित नहीं हो पाते हालांकि इससे सृजित प्रौद्योगिकियों की कृषि विकास में बड़ी परिवर्तनकारी भूमिका होती है। इस प्रकार, वैज्ञानिक शोधपत्रों पर आधारित मेट्रिक्स अक्सर लागू नहीं होते हैं।

भारतीय समाज में कृषि की प्रासंगिकता को देखते हुए एनईपी—2020 में कृषि पर पर्याप्त जोर नहीं दिया गया है और कृषि शिक्षा के लिए बिना किसी नए प्रोत्साहन के इसमें कृषि शिक्षा का केवल संक्षेप में उल्लेख किया गया है।

मौजूदा कृषि शिक्षा प्रणाली NEP—2020 में निर्धारित मूलभूत सिद्धांतों का सम्मान करती है। हालांकि, कृषि में समग्र नामांकन अनुपात में वृद्धि संभव नहीं है क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय (एयू) एक पैशेवर डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान हैं। कृषि विश्वविद्यालयों के ट्रिपल अधिदेश (अनुसंधान—शिक्षण—विस्तार) को देखते हुए एनईपी—2020 द्वारा अनुशंसित छात्र—शिक्षक अनुपात पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

वर्चुअल प्लेटफॉर्म, क्लास रूम टीचिंग की जगह नहीं ले सकते क्योंकि कृषि में अधिकांश कौशलपूर्ण तकनीकों (स्किल) को सीखने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल होता है।

पारंपरिक विश्वविद्यालयों सहित राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) के औपचारिक संपर्क को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि डिग्री हासिल करने के लिए छात्र, हस्तांतरणीय क्रेडिट हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों में नामांकन करने में सक्षम हो सकें।

लुधियाना चैप्टर के तत्वावधान में, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के रोपड़, दोआबा, मोगा एवं होशियारपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों ने पराली जलाने एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के मुद्दे पर स्कूली छात्रों को जागरूक करने के लिए ‘फसल अवशेष प्रबंधन’ पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में छात्रों को उन उपचारात्मक उपायों से अवगत कराया गया जो कृषि प्रणालियों की संवहनीयता से समझौता किए बिना अपनाए जा सकते हैं।

पुणे चैप्टर ने ‘महाराष्ट्र कृषि में अजैविक तनाव प्रबंधन’ पर भाकृअनुप – राष्ट्रीय अजैविक तनाव प्रबंधन संस्थान (एनआईएसएम) एवं कृषि विज्ञान में अजैविक तनाव अनुसंधान समिति (सरस) के साथ एक पैनल चर्चा का आयोजन किया। परिचर्चा की अध्यक्षता अकादमी के अध्येता (फेलो) एवं एमपीकेवी, राहुङी के पूर्व कुलपति डॉ. वाई. एस. नेरकर ने की।



इस चर्चा में निम्नलिखित सिफारिशें उभरीं:

1. फूलों की खेती में गुणवत्ता एवं मूल्यवर्धन पर अजैविक दबावों के प्रभावों का आकलन करके प्रौद्योगिकियों को विकसित किया जाना चाहिए।

2. अनुसंधान में हाल में हुई प्रगति का उपयोग करके प्याज में सूखा एवं जल भराव के प्रति सहिष्णुता को बढ़ाया जाना चाहिए।
3. एक्सपोर्ट क्वालिटी (निर्यात गुणवत्ता) वाले अनार उत्पादन के लिए सेंसर आधारित सिंचाई एवं फर्टिगेशन प्रौद्योगिकियों को मानकीकृत किया जाना चाहिए।
4. अंगूरों में अजैविक दबावों को कम करने के लिए इमेज—समर्थित तकनीकों का विकास किया जाना चाहिए।
5. अजैविक दबावों को कम करने के लिए पशुधन संबंधित आकस्मिक योजनाएँ विकसित की जानी चाहिए।
6. संरक्षित खेती की दशा में विभिन्न फसलों की अजैविक तनाव प्रतिक्रियाओं का आकलन किया जाना चाहिए और उपयुक्त शमन रणनीति विकसित की जानी चाहिए।
7. तनावग्रस्त क्षेत्रों में मृदा जैविक कार्बन एवं तनाव को कम करने वाले यौगिकों को बढ़ाने के लिए सूक्ष्मजैविक उपायों को मानकीकृत किया जाना चाहिए।
8. अजैविक तनावों के प्रति विशिष्ट गुणों एवं जीन तथा आंकड़ों के प्रबंधन एवं विश्लेषण हेतु मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के उपयोग की पहचान की जानी चाहिए।
9. अजैविक दबाव के प्रति सहनशीलता हेतु उन्नत तकनीकों जैसे जीन—एडिटिंग एवं मार्कर—समर्थित तकनीकों सहित पारंपरिक प्रजनन विधि के प्रयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

वाराणसी चैप्टर ने माइक्रोटेक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, वाराणसी के बी.एससी. (एजी) के छात्रों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों की आय एवं पोषण सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अल्प-दोहित एवं गौण सब्जियों की संभावना एवं भूमिका पर एक वार्ता आयोजित की गई। राजकीय इंटर कॉलेज, जखिनी, वाराणसी में 11वीं एवं 12वीं कक्षा में विज्ञान और कृषि के छात्रों के लिए कृषि एवं संबद्ध विज्ञान में कैरियर के अवसरों पर एक विज्ञान जागरूकता अभियान का भी आयोजन किया गया।

सम्पर्क

अकादमी अपने अधिकांश कार्यक्रमों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य अनुसंधान संगठनों/एनजीओ के माध्यम से कार्यान्वित करती है जिनके साथ अकादमी के मजबूत संबंध हैं। इन संगठनों में कार्यरत अकादमी के फैलो (अध्येताओं) द्वारा इन संपर्कों को और अधिक मजबूत किया जाता है। अकादमी ने हाल ही में भारत की अन्य विज्ञान अकादमियों जैसे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए), भारतीय विज्ञान अकादमी, बैंगलुरु,

भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद और नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के साथ (ए) देश में विज्ञान की बेहतर सामान्य समझ और (बी) देश के सामने आने वाले अग्रणी मुद्दों की पहचान जिसमें विज्ञान और वैज्ञानिकों की हिस्सेदारी है से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु सम्पर्क स्थापित करने की दिशा में उचित कदम उठाए हैं। अकादमी ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष कार्यक्रम 2020 (STIP 2020) को तैयार करने की दिशा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को योगदान (इनपुट) दिया है। ये जानकारियां (i) विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेषों में सुधार, (ii) वर्तमान एवं भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए कृषि शिक्षा प्रणाली में सुधार तथा (iii) प्रशासनिक और प्रबंधन सुधार से संबंधित हैं।

संस्थागत सदस्यता

ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान जो अकादमी के उद्देश्यों से सम्बद्ध गतिविधियों में शामिल हैं, इस अकादमी के संस्थागत सदस्य बनने के पात्र हैं। इसके लिए उन्हें नास द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों के लिए नास (नास) कॉर्पस फंड के सतत दीर्घकालिक समर्थन के लिए 10 लाख रुपये का योगदान करना अपेक्षित है। 31 मार्च, 2021 तक ऐसे 35 संस्थागत सदस्यों को शामिल किया गया है।

उत्कृष्टता की पहचान (2021)

नए अध्येता

भाग I: फसल विज्ञान

डॉ. एस. गोपाल कृष्ण

प्रधान वैज्ञानिक (चावल प्रजनन), आनुवंशिकी प्रभाग, भाकृअनुप-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (नई दिल्ली)

डॉ. संजीव गुप्ता

सहायक महा निदेशक (ओपी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (नई दिल्ली)

डॉ. एफ. हुसैन

प्रधान वैज्ञानिक एवं कार्यक्रम लीडर (मक्का), आनुवंशिकी प्रभाग, भाकृअनुप-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (नई दिल्ली)

डॉ. डी. आर. मालवीय

पूर्व प्रभागाध्यक्ष, भाकृअनुप-भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

डॉ. (सुश्री) एन. सरला

भाकृअनुप राष्ट्रीय प्रोफेसर (सेवानिवृत्त), हैदराबाद, (तेलंगाना)

डॉ. राम केवल सिंह

सहायक महा निदेशक (व्यावसायिक फसलें), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (नई दिल्ली)

भाग II: उद्यान विज्ञान

डॉ. एन. राय

प्रधान वैज्ञानिक, फसल सुधार विभाग, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

डॉ. ब्रजेश सिंह

प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभागाध्यक्ष, सीपीबी एवं पीएचटी प्रभाग, भाकृअनुप-केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला (हिमाचल प्रदेश)

डॉ. (सुश्री) एस. उमा

निदेशक, भाकृअनुप-राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, त्रिची (तमिल नाडु)

भाग III: पशु विज्ञान

डॉ. ए. मित्रा

निदेशक, भाकृअनुप- केंद्रीय गोवंश पशु अनुसंधान संस्थान, ग्रास फार्म रोड, मेरठ (उत्तर प्रदेश)

डॉ. बी. एम. नवीन

प्रधान वैज्ञानिक, भाकृअनुप- राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र, चैंपीचेला, बॉड उप्पल पोस्ट, हैदराबाद (तेलंगाना)

डॉ. आशीष के. सिंह

प्रधान वैज्ञानिक, डेयरी प्रौद्योगिकी प्रभाग, भाकृअनुप- राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल (हरियाणा)

डॉ. डी. सिंह

प्रभागाध्यक्ष, पशु जैवरसायन प्रभाग, भाकृअनुप- राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल (हरियाणा)

भाग IV: मत्स्य विज्ञान

डॉ. पांडियन कृष्ण

प्रधान वैज्ञानिक (कृषि अनुसंधान प्रबंधन), अनुसंधान प्रणाली प्रबंधन प्रभाग, भाकृअनुप- राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, हैदराबाद, (तेलंगाना)

डॉ. एस. मैथ्यू

प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभागाध्यक्ष, जैवरसायन एवं पोषण प्रभाग, भाकृअनुप— केंद्रीय मात्रियकी प्रौद्योगिकी संस्थान, कोच्ची (केरल)

भाग V: प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विज्ञान

डॉ. डी. आर. विश्वास

प्रधान वैज्ञानिक, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन प्रभाग, भाकृअनुप—भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (नई दिल्ली)

डॉ. प्रमीला कृष्णन

प्रभागाध्यक्ष, कृषि भौतिकी प्रभाग, भाकृअनुप—भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (नई दिल्ली)

डॉ. वी. के. मिश्रा

निदेशक, भाकृअनुप पूर्वोत्तर पर्वतीय कृषि अनुसंधान परिसर, उमियम (मेघालय)

डॉ. एम. मोहांती

प्रधान वैज्ञानिक, भाकृअनुप—भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल (मध्य प्रदेश)

डॉ. सी.एम. परिहार

वरिष्ठ वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान प्रभाग, भाकृअनुप—भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (नई दिल्ली)

भाग VI: पादप सुरक्षा विज्ञान

डॉ. एस. जोगिया

सहायक प्रोफेसर एवं समन्वयक, पादप स्वास्थ्य देखरेख एवं नैदानिक केंद्र, जैवप्रौद्योगिकी एवं सूक्ष्मजीवविज्ञान का स्नातकोत्तर प्रभाग, कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड (कर्नाटक)

डॉ. पी. के. मुखर्जी

निदेशक, जैवसंसाधन एवं सतत विकास संस्थान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, टेक्येलपट, इम्फाल (मनीपुर)

डॉ. एम. के. नाइक

कुलपति, कृषि एवं उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवामोगा (कर्नाटक)

डॉ. एम. एस. सहरन

प्रधान वैज्ञानिक, पादप रोग विज्ञान प्रभाग, भाकृअनुप—भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (नई दिल्ली)

भाग VII : कृषि इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी

डॉ. दिलीप जैन

प्रभागाध्यक्ष, कृषि इंजीनियरिंग एवं नवीकरण ऊर्जा प्रभाग, भाकृअनुप—केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, जोधपुर (राजस्थान)

डॉ एच. रहमान

प्रोफेसर, कृषि और खाद्य इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर (पश्चिम बंगाल)

भाग VIII: सामाजिक विज्ञान

डॉ. आर.सी. अग्रवाल

उप महानिदेशक (कृषि शिक्षा), कृषि शिक्षा प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (नई दिल्ली)

डॉ. नवीन पी सिंह

सदस्य (सरकारी), कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (नई दिल्ली)

डॉ. जी. एम. सुब्बाराव

वैज्ञानिक ई एवं प्रमुख, पोषण सूचना, संचार एवं स्वास्थ्य शिक्षा (एनआईसीएचई) प्रभाग, आईसीएमआर-राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद (तेलंगाना)

प्रवासी अध्येता (फैलो)

डॉ. विजय कुमार गुप्ता

सीनियर फेलो एवं ग्रुप लीडर, सेंटर फॉर सेफ एंड इम्प्रूव्ड फूड्स एंड बायोरिफाइनिंग एंड एडवांस्ड मैटेरियल्स रिसर्च सेंटर, स्कॉटलैंड रुरल कॉलेज, स्कॉटलैंड, यूके

डॉ. इंद्रजीत चौबे

डीन एवं निदेशक, कृषि महाविद्यालय, स्वास्थ्य एवं प्राकृतिक संसाधन, प्रोफेसर—प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण विभाग, कनेक्टिकट विश्वविद्यालय, यूएसए

उत्सोखियेटशिप

डॉ. बी. बी. बसाक

वैज्ञानिक, भाकृअनुप-ओषधीय एवं सगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय, बोरियावी, आनंद (गुजरात)

विदेशी फैलो

डॉ. रवि नायडू

सीईओ एवं प्रबंध निदेशक, सीआरसी केयर एंड ग्लोबल इनोवेशन चेयर तथा विज्ञान संकाय, न्यूकैसल विश्वविद्यालय, कैलाघन, ऑस्ट्रेलिया

डॉ. ह्यूज डब्ल्यू. प्रिचार्ड

प्रधान वैज्ञानिक लीडर, रॉयल बोटेनिक गार्डन, क्यू वेकहर्स्ट प्लेस, आर्डिंगली, यूके

डॉ. वी. आचार्य

वरिष्ठ वैज्ञानिक, जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग, सीएसआईआर-हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान, पालमपुर (हिमाचल प्रदेश)

डॉ. के. चक्रवर्ती

वैज्ञानिक (वरिष्ठ वेतनमान), फसल कार्यिकी एवं जैवरसायन प्रभाग, भाकृअनुप-राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, विद्याधरपुर, कटक (ओडिशा)

डॉ. डी.एम. फिरके

वरिष्ठ वैज्ञानिक (कृषि कीटविज्ञान), भाकृअनुप-पुष्पसंवर्द्धन अनुसंधान निदेशालय, मुंडावा, पुणे (महाराष्ट्र)

डॉ. आर. गिरि

सहायक प्रोफेसर, स्कूल ॲफ बेसिक साइंसेज, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मंडी, कामंड परिसर, जिला मंडी (हिमाचल प्रदेश)

डॉ. एस. हाती

सहायक प्रोफेसर, डेयरी सूक्ष्मविज्ञान प्रभाग, एसएमसी कॉलेज ॲफ डेयरी साइंस, आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद (ગुજरात)

डॉ. एस. एल. जाट

वैज्ञानिक (वरिष्ठ वेतनमान), भाकृअपनुप-भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, दिल्ली इकाई (नई दिल्ली)

डॉ. एस. के. झा

वरिष्ठ वैज्ञानिक, आनुवंशिकी प्रभाग, भाकृअनुप-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (नई दिल्ली)

डॉ. टी.के. कोली

वैज्ञानिक, सामाजिक-आर्थिक एवं प्रसार प्रभाग, भाकृअनुप-पूर्वी क्षेत्र अनुसंधान परिसर, भाकृअनुप परिसर, पटना (बिहार)

डॉ. एस. मंडल

वैज्ञानिक (एसजी), भाकृअनुप— केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, नवीबाग, बेरासिया रोड, भोपाल (मध्य प्रदेश)

डॉ. सुरेन्द्र सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर, सूक्ष्मजीवविज्ञान प्रभाग, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)

द्विवार्षिक 2019-2020 के दौरान अकादमी द्वारा प्रदत्त पुरस्कार

नास द्वारा 13 नवंबर, 2021 को बीएचयू वाराणसी में 15वीं एएससी के दौरान निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

स्मारक / व्याख्यान पुरस्कार

डॉ. बी. पी. पाल अवार्ड

प्रोफेसर रतन लाल, मृदा विज्ञान के विशिष्ट विश्वविद्यालय प्रोफेसर, द ओहयो स्टेट यूनिवर्सिटी, कोलम्बस, यूएसए

डॉ. के. रमेया अवार्ड

डॉ. ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, निदेशक, भाकृअनुप— गेहूं एवं जौ अनुसंधान निदेशालय, करनाल, हरियाणा

डॉ. के. सी. मेहता अवार्ड

प्रोफेसर एस. आर. निरंजन, पूर्व-कुलपति एवं प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, जैवप्रौद्योगिकी अध्ययन प्रभाग, मैसूर विश्वविद्यालय, मानसगंगोत्री, मैसूर, कर्नाटक

डॉ. एम. एस. रंधावा अवार्ड

डॉ. राकेश चंद्र अग्रवाल, उपमहानिदेशक (कृषि शिक्षा) एवं राष्ट्रीय निदेशक, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना, भाकृअनुप, नई दिल्ली

डॉ. एन. एस. रंधावा अवार्ड

डॉ. हिमांशु पाठक, निदेशक, राष्ट्रीय अजैविक तनाव प्रबंधन संस्थान, पुणे, महाराष्ट्र

डॉ. पी. भट्टाचार्य अवार्ड

डॉ. मनमोहन सिंह चौहान, निदेशक, भाकृअनुप— राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा

डॉ. ए. बी. जोशी स्माकर लेक्चर अवार्ड

डॉ. आर. एस. परोदा, अध्यक्ष, ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रिकल्चरल साइंसेज, नई दिल्ली

प्रतिभा अवार्ड (एंडाउमेंट अवार्ड)

डॉ. एल. सी. सिक्का एंडाउमेंट अवार्ड

डॉ. सी. एन. रविशंकर, निदेशक, भाकृअनुप— केंद्रीय मात्स्यकी प्रौद्योगिकी संस्थान, कोच्ची, केरल

स्मारक / व्याख्यान पुरस्कार

डॉ. (सुश्री) प्रेम डुरेजा एंडाउमेंट अवार्ड	डॉ. सुब्बारथ्या उमा, निदेशक, भाकृअनुप-राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, त्रिची, केरल
डॉ. एन.जी.पी. राव एंडाउमेंट अवार्ड	डॉ. राम केवल सिंह, एडीजी (वाणिज्यिक फसलें), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

मान्यता अवार्ड

पादप सुधार	डॉ. सुदेश कुमार यादव, वैज्ञानिक—एफ, सीआईएबी, मोहाली
पादप सुरक्षा	डॉ. सुप्रिया चक्रवर्ती, प्रोफेसर (वायरोलॉजी), जेएनयू, नई दिल्ली
मृदा, जल एवं पर्यावरणीय विज्ञान	डॉ. अरविन्द कुमार शुक्ला, परियोजना समन्वयक (सूक्ष्मपोषक तत्व), आईआईएसएस, भोपाल
पशु विज्ञान	डॉ. काजल चक्रवर्ती, वरिष्ठ वैज्ञानिक, सीएमएफआरआई, कोच्ची
कृषि इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी	डॉ. सी. आर. मेहता, निदेशक, सीआईएई, भोपाल
सामाजिक विज्ञान	डॉ. ए. आर. राव, एडीजी (पीआईएम), भाकृअनुप, नई दिल्ली

युवा वैज्ञानिक पुरस्कार

पादप सुधार	डॉ. रंजीत कुमार एल्लुर, वैज्ञानिक, आनुवंशिकी प्रभाग, आईएआरआई, नई दिल्ली
पादप सुरक्षा	डॉ. सुशील कुमार शर्मा, वैज्ञानिक (पादप रोगविज्ञान), आरसीएनईएचआर, इम्फाल
मृदा, जल एवं पर्यावरण विज्ञान	डॉ. विजय सिंह मीणा, वैज्ञानिक (एसएस), वीपीकेएएस, अल्मोड़ा
पशु विज्ञान	डॉ. मोनिका सैनी, वैज्ञानिक—I, एआईआईएमएस, नई दिल्ली
कृषि इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी	डॉ. आर. पांडिसेल्वम, वैज्ञानिक, सीपीसीआरआई, कासरगौड़
सामाजिक विज्ञान	डॉ. शिवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, वैज्ञानिक (वरिष्ठ वेतनमान), एनआईएपी, नई दिल्ली

*युवा वैज्ञानिक अवार्ड वर्ष 2020 से प्रत्येक वर्ष दिए जाएंगे।

संस्थापना दिवस उवं वार्षिक आम सभा

नव निर्वाचित अध्येताओं (फैलो) द्वारा प्रस्तुतीकरण

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (नास) के नवनिर्वाचित अध्येताओं ने 22–25 जून, 2020 के दौरान चार सत्रों में अपनी प्रस्तुतियाँ ऑनलाइन दीं। फसल विज्ञान, बागवानी विज्ञान, पशु विज्ञान एवं मत्स्य विज्ञान के निर्वाचित अध्येताओं की प्रस्तुतियों की अध्यक्षता डॉ. ए. के. श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष, नास द्वारा एवं इन सत्रों की सह-अध्यक्षता डॉ. ए. के. सिंह, सचिव, नास द्वारा की गई। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, पौध संरक्षण, कृषि इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक विज्ञान के निर्वाचित अध्येताओं द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण की अध्यक्षता डॉ. जे. सी. कत्याल, उपाध्यक्ष, नास तथा सह-अध्यक्षता डॉ. पी. के. जोशी, सचिव, नास द्वारा की गई।

अध्यक्षीय संबोधन

डॉ. टी. महापात्र ने 27वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) में अध्यक्षीय संबोधन प्रस्तुत किया। अकादमी द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त ख्याति के लिए उन्होंने अकादमी के संस्थापक अध्येताओं, सभी पूर्व अध्यक्षों और सभी अध्येताओं (फैलोशिप) की सराहना की। उन्होंने विशेषकर प्रो. वी. एल. चोपड़ा का उल्लेख किया जो कोविड 19 महामारी के दौरान दिवंगत हो गए। उन्होंने प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन, जिन्होंने 7 अगस्त, 2020 को अपने जीवन के 95 वर्ष पूरे किए का भी अभिनंदन किया। उन्होंने विशेष रूप से अध्येताओं (फेलोशिप) से और अधिक सक्रिय होने की अपील की ताकि अकादमी भविष्य में और अधिक उत्कृष्टता प्राप्त कर सके। उन्होंने कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों जैसे – बीज नीति, कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, जीनोम एडिटेड जीवों हेतु दिशानिर्देश तथा उर्वरक सब्सिडी के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पर सरकार को समयोचित जानकारी प्रदान करने में अकादमी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कृषि क्षेत्र में हासिल किए गए निरंतर विकास पर प्रकाश डाला, जो कि कोविड महामारी के दौरान भी काफी हद तक अप्रभावित रहा था। उन्होंने अध्येताओं को याद दिलाया कि राष्ट्र ने 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है, जो तभी संभव हो सकेगा जब कृषि क्षेत्र से अर्थव्यवस्था में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक योगदान होगा। इस संदर्भ में उन्होंने उपयुक्त नीतियों और दिशा-निर्देशों को विकसित कर प्रभावी रूप से योगदान करने के लिए अध्येताओं का आह्वान किया। उन्होंने विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता का उल्लेख किया – समुद्री संसाधनों का दोहन, समुद्री शैवाल की खेती, मोती की खेती (पर्ल कल्चर), कदन्न (पोषक-अनाज) को मुख्य धारा में लाना, गैर-गोजातीय दूध और उनके उत्पाद, चुनिंदा जैविक उत्पाद, कृषि में विविधीकरण एवं मूल्य शृंखला, कृपोषण, एआई जैसी उन्नत युक्तियों का उपयोग और एसडीजी को प्राप्त करना। उन्होंने कहा कि मांग-आधारित कृषि पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। उन्होंने नवनियुक्त अध्येताओं एवं एसोसियेट को बधाई दी और समग्र अध्येताओं के प्रति आभार प्रकट किया।

संरक्षण दिवस समारोह

कोविड 19 पर पैनल चर्चा : कृषि में इसका प्रभाव एवं न्यू नार्मल (संयोजक : डॉ. पी. के. जोशी एवं डॉ. पी. उस. बड़थल)

अकादमी ने अपने स्थापना दिवस पर 5 जून, 2020 को कृषि पर कोविड –19 आपदा के परिणामों तथा महामारी के बाद कृषि विकास को बनाए रखने हेतु तकनीकी एवं नीतिगत समाधानों पर एक वर्चुअल पैनल चर्चा का आयोजन किया। इस पैनल चर्चा की सह–अध्यक्षता डॉ. त्रिलोचन महापात्र, अध्यक्ष, नास और डॉ. मंगला राय, पूर्व अध्यक्ष, नास ने की। इस बात पर आम सहमति थी कि कोविड–19 महामारी ने दुनिया भर में लाखों गरीबों के जीवन एवं आजीविका को बुरी तरह प्रभावित किया है। पूरी दुनिया अनेक प्रकार के निवारक उपायों द्वारा इस महामारी के एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलने को रोकने के लिए संघर्ष कर रही है, जिसमें साफ–सफाई, फेस–मास्क तथा सामाजिक दूरी शामिल है। अधिकांश देशों ने इसके प्रसार को रोकने के लिए लोगों, वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन पर लॉकडाउन और अनेक प्रकार के सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। इससे आर्थिक गतिविधियां लगभग पूरी तरह से ठप हो गई हैं। भारत में 25 मार्च, 2020 को लॉकडाउन लगाया गया और 1 जून, 2020 से तीन चरणों में अन–लॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी कोविड–19 से प्रेरित मंदी के दबाव में है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2020–21 में अर्थव्यवस्था के 3 से 5% के बीच सिकुड़ने का अनुमान है। यह देखा गया है कि इससे कृषि क्षेत्र के बहुत अधिक प्रभावित होने की संभावना नहीं है और इसके लगभग 3% की महत्वपूर्ण दर से बढ़ने का पूर्वानुमान लगाया गया है। सामान्य तौर पर, कृषि एवं कृषि–व्यवसाय के क्षेत्र में तकनीकों, सहायक सेवाओं, विपणन, व्यापार, वित्तपोषण, शासन, उपभोक्ताओं की पसंद आदि से संबंधित नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पैनल चर्चा की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थीं:

लॉकडाउन के कारण प्रवासी श्रमिकों को बड़े पैमाने पर पलायन कर अपने गांवों में वापस जाने को मजबूर होना पड़ा तथा महामारी के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बाजारों में असंतुलन एक नई सामान्य बात (ए न्यू नार्मल) होगी। पंजाब एवं हरियाणा जैसे राज्यों को श्रमिकों की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा लेकिन इससे राज्य सरकारों को धान के स्थान पर कम श्रम एवं कम पानी वाली फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने का अवसर भी मिलेगा। इसके विपरीत बिहार, ओडिशा एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में रिवर्स माइग्रेशन (घर वापिसी) के कारण अत्यधिक रोजगार दबाव का सामना करना पड़ेगा। ऐसे राज्यों को श्रम–प्रधान उच्च मूल्य वाली कल्याणकारी फसलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

कृषि में निवेश को आकर्षित करने तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु एक सक्षम कृषि–व्यवसाय माहौल विकसित किए जाने की आवश्यकता है। नए अवसरों की योजना बनाते हुए तदनुसार सार्वजनिक–निजी भागीदारी को जरूरत–आधारित कृषि–संरचनाओं और मूल्य श्रृंखलाओं

के लिए सुजित करना अपेक्षित है। खाद्य आधारित मौजूदा एमएसएमई को आधुनिक बनाने और कच्चे माल हेतु सीधे किसानों के साथ जोड़ने की जरूरत है। उनकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग एवं प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला उन्हें एक न्यू नार्मल (नए सामान्य) में रूपांतरित कर सकती है।

श्रमिकों की घर वापसी का उन क्षेत्रों में कृषि पर जबरदस्त रोजगार का दबाव डालेगा जहां श्रमिक वापस लौटे हैं। हालांकि, मनरेगा रोजगार के कुछ अवसर अवश्य प्रदान करता है किंतु यह पर्याप्त नहीं है। ऐसे श्रमिकों के लिए आय सृजन करने वाली विशेष योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, प्रवास और इसकी विपरीत स्थितियों को देखते हुए सरकार को तुरंत ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना लागू करनी चाहिए जिससे देश में कहीं भी श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। केवल उत्पादन बढ़ाने की बजाय कई अन्य लक्ष्यों जैसे आय में वृद्धि, पोषण में सुधार, पारिस्थितिकी को संरक्षित करने और पर्यावरण के संरक्षण पर ध्यान देने के लिए अनुसंधान में बदलाव करना होगा। प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण से समझौता किए बिना कृषि को एक आकर्षक उद्यम बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए।

भोजन, पशु आहार एवं चारे की आगामी मांगों को पूरा करने के लिए कृषि अनुसंधान एजेंडे को प्राथमिकता देने की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रो-रोबोटिक्स, नैनो साइंस, क्लोनिंग और ड्रोन एनालिटिक्स की भूमिका से भविष्य में कृषि—सलाह, रोग/कीट निगरानी एवं सर्विलांस के द्वारा कृषि अनुसंधान में कई गुना विस्तार लाया जा सकता है। इसी प्रकार, प्लांट जीनोमिक्स एवं जीनोम एडिटिंग आगे के शोध के महत्वपूर्ण उपकरण बन जाएंगे। आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) खाद्य पदार्थ और जैव—संपूरण विभिन्न प्रकार के विषाणुओं (वायरस) के विरुद्ध प्रतिरक्षा विकसित करने के लिए किस्मों/संकरों की नस्ल के लिए एक नई सामान्य प्रक्रिया (न्यू नार्मल) तैयार करनी होगी।

‘वन हेल्थ’ की संकल्पना को सही मायने में बढ़ावा देना होगा जिसके तहत मनुष्यों, पशुओं एवं पौधों के बीच उनके संयुक्त वातावरण में अंतःक्रिया पर ध्यान दिया जाता है। कृषि अनुसंधान में पोषण एवं स्वास्थ्य हेतु प्रजनन तथा तनाव प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। पशु एवं चिकित्सा विज्ञान के साथ फसल विज्ञान के क्षेत्र में और अधिक सहयोग वांछनीय होगा। मानव, वित्तीय एवं ज्ञान सहित सभी संसाधनों को एकत्रित करने और उनका साझा उपयोग करने के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करते हुए सामान्य अनुसंधान मच विकसित करना होगा।

सूचना, सेवा एवं प्रौद्योगिकियों के समय पर प्रसारण और प्रसार के लिए सूचना के पिछले एवं अग्रवर्ती प्रवाह तथा आईसीटी का लाभ उठाने के लिए बाजार—उन्मुख कृषि विस्तार सेवाओं के लिए निजी क्षेत्र को आकर्षित करना होगा।

अकादमी ने विचार—विमर्श के आधार पर “कोविड -19 महामारी: प्रभाव एवं कृषि में नई सामान्य प्रक्रिया (न्यू नार्मल) पर एक ‘नीतिपत्र सार 8’ प्रकाशित किया है।

27वीं वार्षिक आम सभा (उज्जीतुम) के कार्यवृत्त के अंश

अकादमी की 27वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) 13 अगस्त, 2020 को अकादमी के अध्यक्ष डॉ. त्रिलोचन महापात्र की अध्यक्षता में वर्चुअल रूप में आहूत की गई। एजीएम में 200 से अधिक फैलो (अध्येताओं) ने भाग लिया जिनमें पूर्व अध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष एवं अकादमी के पदाधिकारी शामिल हुए। पिछली एजीएम के पश्चात दिवंगत हुए सदस्यों डॉ. के. एस. गिल, डॉ. सी. गोपालन, डॉ. डी. आर. भुम्बला, डॉ. एस. एम. विरसानी, डॉ. एन. एन. सिंह, डॉ. एस. कदम, डॉ. डी. एस. बरार, डॉ. पी. के. छोंकर, डॉ. पॉल थॉमस, डॉ. वी. एल. चोपड़ा, डॉ. पी. एन. भट, डॉ. वाई. पी. एब्रॉल और डॉ. वी. डी. कौशिक के सम्मान में एक मिनट का मौन रखा गया।

नास के सचिव डॉ. अनिल के. सिंह ने वर्चुअल जीबी बैठक में सम्मिलित गणमान्य व्यक्तियों, फैलोशिप एवं एसोसिएट्स का स्वागत किया। अकादमी के अध्यक्ष डॉ. त्रिलोचन महापात्र ने भी वार्षिक आम सभा की बैठक में अकादमी के नवनिर्वाचित अध्येताओं एवं एसोसिएट्स सहित सभी सम्मानित अध्येताओं का स्वागत किया। बैठक की कार्यवाही डॉ. अनिल के. सिंह द्वारा सचिव की रिपोर्ट, डॉ. आर. के. जैन द्वारा ऑडिट एवं लेखा रिपोर्ट, डॉ. कुसुमाकर शर्मा द्वारा संपादक की रिपोर्ट और डॉ. अनिल के. सिंह द्वारा (डॉ. यू.एस. सिंह की अनुपस्थिति में) विदेश सचिव की रिपोर्ट प्रस्तुत करके प्रारंभ हुई। वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षित लेखा 2019–20 सहित इन सभी रिपोर्टों को सदन द्वारा स्वीकृत एवं अंगीकृत किया गया। एजीएम ने 5 जून, 2019 को आयोजित 26वीं वार्षिक आम सभा की बैठक के कार्यवृत्त की भी पुष्टि की, इसके अलावा पिछले एजीएम के बाद से कार्यकारी परिषद द्वारा लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों में वर्ष 2020–21 के लिए अकादमी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, 2020 के दौरान संचालित कार्यक्रम तथा नास की गतिविधियों के लिए सुझाए गए क्षेत्र सम्मिलित थे।

अध्येताओं/उसोसियेट का प्रवेश समारोह

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (नास) के सचिव डॉ. अनिल के. सिंह एवं डॉ. पी. के. जोशी ने वर्ष 2020 के दौरान नव निर्वाचित अध्येताओं एवं एसोसिएट्स का औपचारिक प्रवेश समारोह आयोजित किया। निर्वाचित फैलो एवं एसोसिएट्स के नाम पुकारे गए और उनके साइटेशन (उद्घरण) पढ़े गए, और नास के अध्यक्ष ने निहित अधिकारों का उपयोग करके विभिन्न सेक्सन में 29 अध्येताओं, 2 विदेशी अध्येताओं, 3 प्रवासी अध्येताओं और 11 एसोसिएटों को ऑनलाइन स्वीकृति प्रदान की।

सामान्य विचार विमर्श

सम्मानित अध्येताओं (फैलोशिप) ने सामान्य चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा कई प्रासंगिक मुद्दों पर अपने सुझाव दिए। अध्येताओं ने कुछ विचार–मंथन सत्रों का भी प्रस्ताव रखा जिसमें 'रेशम कीट पालन', 'संविदात्मक खेती', 'प्रत्यक्ष लाभ अंतरण' एवं 'पीएम गरीब कल्याण योजना' शामिल हैं। 12वीं कक्षा के बाद कृषि विषय को पहली पसंद के रूप में लोकप्रिय बनाने के प्रयास करने का भी प्रस्ताव किया गया।

प्रकाशन

प्रतिवेदित अवधि के दौरान अकादमी ने निम्नलिखित प्रकाशन निकाले:

नीति / स्टेटस / नीतिगत शोधपत्र

पॉलिसी पेपर 93: कृषि अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक संस्कृति को बढ़ाना

पॉलिसी पेपर 94: कृषि में पारिस्थितिकी सेवाओं का भुगतान

पॉलिसी पेपर 95: खाद्य पदार्थों से होने वाले पशुजन्य रोग

पॉलिसी पेपर 96: कृत्रिम गर्भाधान (एआई) द्वारा पशुधन सुधार

संक्षिप्त नीतिपत्र (पालिसी ब्रीफ)

पॉलिसी ब्रीफ 6: भारत में कीटनाशकों का बेहतर प्रबंधन : नीति दृष्टिकोण

पॉलिसी ब्रीफ 7: जीनोम संशोधित पौधों हेतु विनियामक तंत्र : पादप प्रजनन में सुस्पष्टता एवं गति को बढ़ाना

पॉलिसी ब्रीफ 8: कोविड –19 महामारी : प्रभाव एवं कृषि में नई सामान्य प्रक्रिया (न्यू नार्मल)

पॉलिसी ब्रीफ 9: उर्वरक सहायता का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण : नीतिगत दृष्टिकोण

पॉलिसी ब्रीफ 10: भारत में सतत खाद्य सुरक्षा हेतु बीज विनियमन में सामंजस्य

न्यूजलेटर

नास–समाचार, खंड 20, अंक 2 से 4 एवं खंड 21, अंक 1 (त्रैमासिक)

जर्नल (स्प्रिंजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित)

नास की आधिकारिक जर्नल 'एग्रिकल्चरल रिसर्च' खंड 9, अंक 2 से 4 एवं खंड 10, अंक 1 (त्रैमासिक)

अन्य प्रकाशन

कृषि रूपांतरण – नए भारत की ओर एक कदम

डॉ. टी. महापात्र द्वारा 27वीं वार्षिक आम सभा, 2020 में दिया गया अध्यक्षीय संबोधन

निवार्चित अध्येताओं द्वारा सार का प्रस्तुतीकरण (2020)

नास ईयर बुक एवं ईयर प्लानर 2021

विभिन्न कार्यक्रम उवं बैठकें

नव-वर्ष सम्मेलन

अकादमी ने 1 जनवरी, 2021 को डॉ. टी. महापात्र की अध्यक्षता में नव वर्ष सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सम्मिलित गणमान्य व्यक्तियों में डॉ. पी. के. जोशी, सचिव एवं नव निर्वाचित उपाध्यक्ष डॉ. ए. के. सिंह और सचिव डॉ. के. सी. बंसल सहित अकादमी के अन्य पदाधिकारी सम्मिलित हुए। डॉ. पी. के. जोशी ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों तथा सभी अध्येताओं एवं एसोसिएट का गर्मजोशी से स्वागत किया।

डॉ. टी. महापात्र ने सभी को नव वर्ष में सुरक्षित एवं स्वरक्ष्य रहने की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कोविड-19 महामारी के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की और इसे रोकने में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कामना की कि नया साल सभी के लिए सुरक्षित हो और सभी से इस बीमारी से बचने के सभी आवश्यक निवारक उपाय अपनाने का आग्रह किया।

डॉ. महापात्र ने 2020 में अकादमी की उपलब्धियों की प्रशंसा की और कार्यकारी परिषद (ईसी) एवं सचिवालय के सभी सदस्यों को उनके अथक प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कीटनाशक विधेयक, बीज विधेयक और जैव विविधता अधिनियम (संशोधन) पर भारत सरकार को उपयुक्त जानकारी (इनपुट) प्रदान करने में अकादमी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने तत्काल कार्रवाई के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्रों का भी उल्लेख किया। इनमें कृषि विज्ञान में महिलाओं को मान्यता और पर्याप्त प्रतिनिधित्व, विश्व स्तर पर विशेष रूप से सार्क देशों में अकादमी की दृश्यता और सीमापार रोगों के प्रबंधन की आवश्यकता प्रमुख है। उन्होंने इस बात को दोहराया कि अकादमी को कृषि एवं ग्रामीण विकास नीतियों के कार्यान्वयन में कमियों की पहचान करनी चाहिए और अंतराल को पाटने तथा बदलते सामाजिक-आर्थिक परिवेश के साथ नीतियों को संरेखित करने के उपाय सुझाने चाहिए। अकादमी द्वारा कृषि विज्ञान के महत्व को विशेष रूप से प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से समाज एवं स्कूली बच्चों को प्रासंगिक वैज्ञानिक मुद्दों को व्यापक तौर पर बताए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि अकादमी को समाज के लिए एक मजबूत प्रासंगिक ज्ञान-आधार का निर्माण करना चाहिए। उन्होंने अध्येताओं से अनुरोध किया कि वे क्षेत्रीय चैप्टरों के माध्यम से ज्ञान के प्रसार हेतु अपने विशाल एवं व्यापक अनुभव का उपयोग करने पर जोर दें। उन्होंने कार्यकारी परिषद (ईसी) के नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी एवं विश्वास प्रकट किया कि वे अकादमी को नई ऊँचाइयों पर ले जाएंगे। इसके बाद नवनिर्वाचित अध्येताओं एवं सहयोगियों का स्वागत करके उनका परिचय कराया गया। समारोह के दौरान फैलोशिप एवं एसोसिएटशिप प्रमाणपत्र, 2020 को वैयक्तिक रूप से प्रदान किया गया।

डॉ. ए. के. सिंह ने 2021 के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा की। उन्होंने अकादमी के क्रियाकलापों में और अधिक सुधार के लिए सम्मानित फैलोशिप से सुझाव मांगे। बैठक में उपस्थित

विशिष्ट अध्येताओं के साथ—साथ वर्चुअली भाग ले रहे अध्येताओं ने अकादमी को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक विजिबल (दृश्यमान) बनाने पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

डॉ. पी. के. जोशी ने निवर्तमान पदाधिकारियों एवं कार्यकारी परिषद के सदस्यों को उनके प्रशासनिक एवं शैक्षणिक समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने दोहराया कि केवल विज्ञान एवं नवोन्मेषी कृषि द्वारा ही किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है और इसी में भारत को 'आत्मनिर्भर' एवं कृषि के क्षेत्र में एक अग्रणी देश बनाने की क्षमता निहित है। उन्होंने 2021 के लिए अकादमी द्वारा परिकल्पित निम्नलिखित नए कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण भी दिया— (1) सामयिक मुद्दों पर अधिक संख्या में वैचारिक चर्चाओं का आयोजन, (2) अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ विमर्श, (3) नास गतिविधियों का सरकारी कार्यक्रमों के साथ मुख्य धारा में समावेश, (4) प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नास की दृश्यता, और (5) 15वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन।

प्रो. के. सी. बंसल ने उपरिथित सम्मानित श्रोताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने अध्येताओं के बीच साझेदारी और विमर्श में सुधार हेतु एक वर्चुअल विज्ञान अकादमी की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए बैंचमार्क का उन्नयन किया जाना चाहिए तथा विशिष्ट समकालीन मुद्दों पर विचार—मंथन के लिए कार्य समूह तैयार करके ओपिनियन पेपर (विचार पत्र) विकसित कर उन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित करके वैज्ञानिक एवं नीतिगत मुद्दों पर अकादमी की विजिविलिटी (दृश्यता) को और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है।

इस अवसर पर अकादमी की रणनीतिक / पॉलिसी पेपर, नास ईयरबुक 2021, नास—न्यूज, अक्टूबर—दिसंबर 2019 एवं नास प्लानर, 2020 का विमोचन भी किया गया।

क्षेत्रीय चैप्टरों के संयोजकों की बैठक

क्षेत्रीय चैप्टरों के संयोजकों की एक बैठक 15 फरवरी 2021 को मिलेजुले रूप (वास्तविक एवं वर्चुअल दोनों) में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता डॉ. टी. महापात्र ने की। सभी संयोजकों ने मुख्यालय द्वारा 2020 के लिए प्रस्तावित क्रियाकलापों तथा वर्ष 2021 के दौरान की जाने वाली गतिविधियों पर भी प्रस्तुतिकरण दिया। संयोजकों को यह सुझाव दिया गया कि वे क्षेत्रीय परिदृश्य के प्रलेखीकरण हेतु आम विषयों पर विचार—मंथन सत्रों को आयोजित कर सकते हैं जैसे कि (1) सरकार द्वारा घोषित तीन कृषि अधिनियमों पर दृष्टिकोण, (2) ऐसी वस्तुओं की पहचान जो लोकल टू ग्लोबल (स्थानीय स्तर से वैश्विक स्तर) व्यापार का हिस्सा बन सकती हैं और (3) जलवायु परिवर्तन से संबंधित अजैविक एवं जैविक तनाव संबंधी पहलू।

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (नास) के अध्यक्ष ने क्षेत्रीय चैप्टरों द्वारा संचालित गतिविधियों की सराहना की। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि क्षेत्रीय चैप्टरों को और अधिक जीवंत बनाने के लिए

अधिक प्रभावी एवं प्रभावोन्मुखी गतिविधियों को शुरू किया जा सकता है क्योंकि वे अपने—अपने क्षेत्र में अकादमी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने वर्ष 2021 के लिए क्षेत्रीय चैप्टरों की कार्य—योजना के रूप में निम्नलिखित गतिविधियों का प्रस्ताव दिया।

क्षेत्रीय चैप्टरों को अपने—अपने क्षेत्रों में अकादमी की दृश्यता बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इसे उद्योग, मीडिया और किसानों के प्रतिनिधियों सहित नीति निर्माताओं, प्रशासकों और अन्य हितधारकों के साथ विचार विमर्श करके प्राप्त किया जा सकता है।

विशेषज्ञों को आमंत्रित करके समकालीन विषयों पर विचार-मंथन सत्रों / व्याख्यानों का आयोजन

कृषि क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए युवा छात्रों को प्रेरित करने के लिए कुछ स्कूलों को अपनाना। इसके अलावा, छात्रों को विश्वविद्यालयों / संस्थानों एवं प्रवेश प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करना। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल छोड़ चुके (ड्रॉप—आउट) छात्रों के साथ विचार—विमर्श करके उन्हें अपनी आजीविका हेतु कृषि को एक उद्यम के रूप में अपनाने के लिए तैयार करना।

अधिकांश कृषि विश्वविद्यालयों में संकाय सदस्यों (फैकल्टी) की कमी है। इसलिए अध्येताओं को कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षण एवं अनुसंधान कार्यक्रम के लिए स्वेच्छा से अपनी सेवाएं देने के कार्य पर लगाया जा सकता है।

सामयिक मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने एवं उनके समाधान हेतु संबंधित राज्य सरकारों में सचिव जैसे उच्च स्तरीय अधिकारियों के समक्ष विचार विमर्श हेतु साक्ष्य—आधारित दस्तावेज विकसित करना।

अकादमी के प्रासंगिक नीति पत्रों/संक्षेपों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करके उन्हें विभिन्न हितधारकों को वितरित करना।

अकादमी की वेबसाइट के एक भाग को अनूदित नीति दस्तावेजों के लिए रखा जा सकता है जिसमें क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर नीति—निर्माताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए मुख्य बिंदुओं का सारांश के रूप में उल्लेख किया जा सकता है।

कार्यकारी परिषद की बैठक

प्रतिवेदित वर्ष के दौरान 19 जून, 2020, 10 अगस्त, 2020, 12 नवंबर, 2020, 26 दिसंबर, 2020, 19 फरवरी, 2021 और 11 मार्च, 2021 को कार्यकारी परिषद की कुल 06 बैठकों का नई दिल्ली में आयोजन किया गया। इन बैठकों में विचार किये गए कुछ महत्वपूर्ण मद्दों तथा बैठकों के दौरान लिए गए निर्णयों का विवरण निम्नानुसार हैं:

112वीं बैठक

डॉ. टी. महापात्र की अध्यक्षता में 112वीं बैठक का आयोजन 19 जून, 2020 को ऑनलाइन माध्यम से किया गया, बैठक में परिषद के 20 सदस्यों ने भाग लिया। डॉ. वी. एल. चोपड़ा, डॉ पॉल थॉमस, डॉ पी. के. छोंकर एवं डॉ. पी. एन. भट्ट जो कि इस अकादमी के विशिष्ट अध्येता थे का इस तिमाही के दौरान निधन होने के कारण उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एक मिनट का मौन रखा गया।

डॉ. टी. महापात्र ने अपने प्रारंभिक संबोधन में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों का उल्लेख किया। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान आवश्यक खाद्य वस्तुओं की जरूरतों को पूरा करने में कृषि की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मजदूरों की कमी तथा सस्योत्तर होने वाले नुकसान के बावजूद रबी का उत्पादन ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ और खरीफ की बुवाई का रकबा पिछले साल की तुलना में अधिक था। उन्होंने 2030 तक एसडीजी (SDGs) प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया। उन्होंने विस्थापित प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने और कृषि अनुसंधान एवं विकास द्वारा भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत मिशन में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए पर्याप्त प्रयास करने की जरूरत बताई। उन्होंने, कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, बीज विधेयक, जीन एडिटिंग दिशानिर्देश तथा उर्वरकों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को तैयार करने में अकादमी द्वारा सरकार को समय पर अपने सुझावों को अग्रेषित करने के लिए अकादमी की सराहना की।

प्रोफेसर रमेश चंद, 15वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस (एएससी) के संयोजन सचिव ने एएससी की तारीखों को फिर से निर्धारित करने का अनुरोध किया क्योंकि लॉकडाउन के कारण इसमें अधिक प्रगति नहीं हो सकी। उन्होंने प्रस्तावित कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने में बीएचयू के कुलपति द्वारा पूर्ण सहयोग के आश्वासन के बारे में सूचित किया। कोविड-19 की संभावित स्थिति एवं प्रतिनिधियों के लिए आवास की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, आयोजन सचिव को नवंबर 2021 के दूसरे/तीसरे सप्ताह के दौरान कांग्रेस को फिर से निर्धारित करने की संभावना तलाशने की सलाह दी गई। कार्यकारी परिषद ने प्रोफेसर रमेश चंद एवं डॉ. राकेश सिंह को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया।

कोविड-19 महामारी के कारण एनएएससी परिसर, नई दिल्ली में 4-5 जून, 2020 को निर्धारित एजीएम/स्थापना दिवस कार्यक्रम के स्थगित होने के बारे में कार्यकारी परिषद (ईसी) को सूचित किया गया। तथापि, 5 जून, 2020 को संस्थापना दिवस समारोह के रूप में डॉ. टी. महापात्र एवं डॉ. मंगला राय की सह-अध्यक्षता में एक ऑनलाइन पैनल चर्चा 'कोविड-19 : कृषि पर और नया सामान्य' का आयोजन किया गया जिसके संयोजक डॉ. पी. के. जोशी और डॉ. प्रताप एस. बड़थल थे।

कार्यकारी परिषद ने वैकल्पिक तरीके द्वारा एजीएम 2020 का आयोजन किया। नवनिर्वाचित अध्येताओं की प्रस्तुतियाँ 22 जून से 25 जून, 2020 के बीच वेबिनारों के माध्यम से आयोजित की गईं। फैलोशिप प्रमाणपत्र भी ऑनलाइन प्रदान किए गए।

कार्यकारी परिषद ने 31 दिसंबर, 2020 के बाद रिक्त होने वाले कार्यकारी परिषद के सदस्यों एवं पदाधिकारियों की एक तिहाई संख्या को भरने तथा वर्ष 2020–21 के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए फेलोशिप से सुझाव आमंत्रित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कार्यकारी परिषद ने वर्ष 2019–20 के लिए अकादमी की वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा के लेखा संपरीक्षित विवरण की समीक्षा, जर्नलों की नास स्कोरिंग, वर्ष 2020 के लिए प्राप्त फैलोशिप/एसोसिएटशिप के नामांकन, 2020 के लिए अकादमी की गतिविधियों की योजना एवं अन्य प्रासंगिक विषयों की समीक्षा की तथा अकादमी के क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

113वीं बैठक

इस बैठक का आयोजन 10 अगस्त, 2020 को डॉ. टी. महापात्र की अध्यक्षता में ऑनलाइन किया गया था। सचिव एवं अध्यक्ष द्वारा संक्षिप्त स्वागत करने के पश्चात् कार्यसूची मदों (एजेंडा आइटम) पर विस्तार से चर्चा करके उन्हें अनुमोदित किया गया। अकादमी के उपाध्यक्ष डॉ. जे. सी. कत्याल ने भावी कृषि के लिए रोडमैप तैयार करने हेतु अकादमी की नीति एवं नीतिगत पत्रों से उभरे बिंदुओं की प्रस्तावित समीक्षा पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। कार्यकारी परिषद ने वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा के लेखा संपरीक्षित विवरण को अंगीकृत करने हेतु प्रस्तुत मसौदा प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा, कार्यकारी परिषद ने 2019–2020 द्विवार्षिक के लिए अकादमी के मेमोरियल, एंडोउर्मेंट, मान्यता एवं युवा वैज्ञानिक पुरस्कारों के लिए नामांकित व्यक्तियों में से पुरस्कार विजेताओं के चयन के लिए निर्णायक समितियों के गठन पर विचार किया और स्वीकृति प्रदान की। कार्यकारी परिषद को भारत के नव विज्ञान के निरूपण, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष नीति (एसटीआईपी 2020), प्राप्त फेलोशिप/एसोसिएट्स के नामांकन की स्थिति, वर्ष 2021 के लिए जर्नलों की संशोधित नास स्कोरिंग, कार्यकारी निदेशक एवं कार्यकारी परिषद के पदाधिकारियों व सदस्यों के 1 जनवरी, 2021 से रिक्त पदों को भरने, चालू वर्ष के लिए अकादमी की प्रस्तावित गतिविधियाँ, एजीएम/स्थापना दिवस कार्यक्रम 2020 और 15वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2021 के बारे में सूचित किया गया।

114वीं बैठक

कार्यकारी परिषद की 114वीं बैठक 12 नवंबर, 2020 को डॉ. टी. महापात्र की अध्यक्षता में वर्चुअल मोड में आयोजित की गई। डॉ. ए. के. सिंह, सचिव ने विस्तृत विचार–विमर्श के बाद कार्यकारी परिषद द्वारा समर्थित अनुभागीय समितियों की सिफारिशों प्रस्तुत कीं। इसी प्रकार, वर्ष 2021 के लिए प्रवासी एवं विदेशी अध्येतावृत्ति की सिफारिशों को स्वीकार किया गया। कार्यकारी परिषद ने 1 जनवरी, 2021 से कृषि संबंधी विषयों में कार्यरत 11 युवा वैज्ञानिकों के अकादमी के एसोसिएट्स के रूप में चयन को भी स्वीकृति प्रदान की। कार्यकारी परिषद (ईसी) ने 1 जनवरी, 2021 से होने वाले विभिन्न रिक्त पदों के लिए फेलोशिप से सुझावों की जांच के बाद नास के दिशानिर्देशों के अनुसार रिक्तियों को भरने

के लिए संपूर्ण फैलोशिप का मत जानने के पश्चात नामों की सूची तैयार की। कार्यकारी परिषद को कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति, नास की पत्रिकाओं की 2021 की स्कोरिंग, सीएजी रिपोर्ट— अनुवर्ती कार्रवाई तथा नीति पत्रों की स्थिति/नीति ब्रीफ आदि के बारे में भी अवगत कराया गया।

115वीं बैठक

कार्यकारी परिषद की 115वीं बैठक 26 दिसंबर, 2020 को डॉ. टी. महापात्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें शामिल किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में जनवरी 2021 से पदाधिकारियों/ इसी के सदस्यों/फैलोशिप/एसोसिएट के चयन का अनुसमर्थन तथा अकादमी पुरस्कारों के लिए कार्यक्रम समिति एवं विभिन्न निर्णायक समितियों की सिफारिशों का अनुमोदन शामिल है। यह निर्णय भी लिया गया कि जर्नल स्कोर समिति की सिफारिशों को यथाशीघ्र अनुमोदन हेतु इसी को प्रस्तुत किया जाए।

116वीं बैठक

डॉ. टी. महापात्र की अध्यक्षता में 19 फरवरी, 2021 को यह बैठक मिलेजुले माध्यम अर्थात् वास्तविक उपस्थिति के साथ—साथ ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई। अध्यक्ष ने सभी इसी सदस्यों का और विशेष रूप से नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और कार्यकारी परिषद के सदस्यों का स्वागत किया जिन्होंने 1 जनवरी, 2021 को अकादमी में कार्यभार ग्रहण किया इनमें – डॉ. अनिल के सिंह, उपाध्यक्ष, डॉ. के. सी. बंसल, सचिव, डॉ. (सुश्री) मालविका ददलानी, संपादक, और सदस्यों में डॉ. एम. एस. चौहान, डॉ. एस.के. दत्ता, प्रो. ए. आर. पोडिले और डॉ. (सुश्री) तारु शर्मा शामिल थे। इसी ने डॉ संजय राजाराम को श्रद्धांजलि देने एवं सम्मान प्रकट करने के लिए एक मिनट का मौन रखा। अध्यक्ष ने दोहराया कि अकादमी को वर्तमान सामयिक मुद्दों पर ठोस चर्चा करके नीति निर्माताओं और केंद्र/राज्य सरकारों को साक्ष्य—आधारित समाधान प्रदान करना चाहिए।

प्रोफेसर रमेश चंद, निदेशक, कृषि विज्ञान संस्थान, बीएचयू, विशेष आमंत्रित सदस्य ने 15वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस (एएससी) की तैयारियों पर जानकारी दी। इसी ने विदेशी एवं राष्ट्रीय प्रतिनिधियों हेतु पंजीकरण शुल्क संरचना को मंजूरी दी। तकनीकी कार्यक्रम समिति के सदस्य सचिव डॉ. अनिल के सिंह, 15वीं एएससी एवं उपाध्यक्ष, नास ने संक्षेप में तकनीकी कार्यक्रम के बारे में बताया। अध्यक्ष ने सदस्यों से कुछ समसामयिक विषयों पर सुझाव देने के साथ—साथ कुछ वैशिक शोधकर्ताओं एवं विशेषज्ञों का नाम सुझाने का अनुरोध किया, जिन्हें इसमें आमंत्रित किया जा सकता है।

कार्यकारी परिषद को सूचित किया गया कि 115वीं इसी बैठक में अनुमोदित संशोधित दिशा—निर्देशों के अनुसार, फैलो के चुनाव, एसोसिएट्स के चयन तथा युवा वैज्ञानिक पुरस्कारों के लिए नामांकन फॉर्म एवं दिशानिर्देशों को संशोधित करके वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसी को विभिन्न

मंत्रालयों और विभागों को सौंपे गए दस्तावेजों जैसे विज्ञान से संबंधित सिफारिशें, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार को प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेषी नीति, 2020 (एसटीआईपी 2020) के प्रस्तुत करने के बारे में भी बताया गया।

कार्यकारी परिषद ने (i) फेलो, एसोसिएट्स एवं युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के चयन हेतु आवेदन जमा करने की तिथि को 15 अप्रैल, 2021 तक बढ़ाने और (ii) अकादमी के कार्यकारी निदेशक के पद पर 31 मार्च, 2021 को सेवानिवृत्ति के बाद डॉ संजीव सक्सेना, एडीजी (आईपीआर) के चयन को अनुमोदन प्रदान किया।

117वीं बैठक

11 मार्च, 2021 को संयुक्त माध्यम से एक आपात बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक का एजेंडा 'जीएम खाद्य फसल' मामले में सुप्रीम कोर्ट में 'नास' के शामिल होने पर चर्चा करना था। इस मामले को 13 अप्रैल, 2021 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

सदस्यों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पूर्व में प्रस्तुत साक्ष्य-आधारित जानकारी के समर्थन में अकादमी की सक्रिय भूमिका की सराहना की। यह निर्णय लिया गया कि जीएम खाद्य फसलों के खेतों में परीक्षण हेतु सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक मजबूत मामला पेश करने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्यों को एकत्रित किया जाना चाहिए तथा अन्य विभागों जैसे डीएसटी एवं डीबीटी को भी इस चर्चा में आमंत्रित करने की आवश्यकता है। अपेक्षित जानकारी एकत्र करने के पश्चात उत्तर तैयार करने के लिए प्रो. स्वपन के द्वारा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया।

जर्नल स्कोर समिति

अकादमी द्वारा कृषि एवं उससे संबद्ध विज्ञान के लिए प्रासंगिक एवं प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाओं का प्रत्येक तीन वर्ष में स्वैच्छिक मूल्यांकन किया जाता है। अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत न करने / अपूर्ण जानकारी देने के कारण छूट गई पत्रिकाओं या बाद में नास स्कोर के लिए पात्रता रखने वाली पत्रिकाओं को भी अवसर प्रदान किया जाता है और वार्षिक आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। की गई संस्तुतियों के आधार पर 01 जनवरी, 2021 से प्रभावी नास द्वारा निर्धारित स्कोर जर्नलों की सूची को अद्यतन कर अकादमी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

यहां यह उल्लेख है कि अकादमी द्वारा प्राथमिक रूप से अकादमी के फैलोशिप, एसोसिएटशिप और पुरस्कारों के लिए नामांकित व्यक्तियों के प्रकाशित शोध कार्य का गहन मूल्यांकन करने एवं मूल्यांकन में एकरूपता लाने हेतु एक पारदर्शी और परिमाणात्मक तंत्र विकसित करने के लिए पत्रिकाओं की स्कोरिंग के लिए अकादमी ने यह अभ्यास किया।

नास द्वारा परामर्शी सेवाएं

ब्राम-स्तरीय फसल उपज के आकलन हेतु उपलब्ध वैशिष्टक प्रौद्योगिकी की पहचान हेतु विशेषज्ञ शूप

महालेनोबिस नेशनल क्रॉप फोरकास्ट चेंज सेंटर (एमएनसीएफसी), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अनुरोध पर अकादमी ने ग्राम/खेत स्तर पर फसल उपज के अनुमान हेतु विश्व स्तर पर उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया। इस अध्ययन का मुख्य ध्येय उन प्रौद्योगिकियों की पहचान करना है जो कृषि मंत्रालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समय पर अनुमान प्राप्त करने में सक्षम हों।

फसल विकास मॉडल के साथ रिमोट सेंसिंग एवं मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) जैसे आधुनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने पर जोर दिया गया है। इस परियोजना का परिणाम मंत्रालय द्वारा अपनाए जाने हेतु भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त सबसे प्रभावी तकनीक की पहचान करना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) जैसे सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए इसका उपयोग करना होगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली का प्रभाव

राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली ने देश की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूर्ववर्ती अध्ययनों में कृषि अनुसंधान में निवेश से प्राप्त लाभ (रिटर्न) की बहुत अधिक दरों का संकेत मिलता है। कृषि अनुसंधान द्वारा कुशलता में सुधार (कृषि विकास), किसानों की आय में वृद्धि, रोजगार के अवसर सृजित करने तथा गरीबी को कम करने में अत्यधिक योगदान दिया है। प्रतिस्पर्धात्मकता में तेजी लाने और विदेशी मुद्रा से प्राप्त आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी— आधारित विकास अनिवार्य है। पिछले पांच दशकों के दौरान कई तकनीकों को जारी किया गया तथा किसानों ने अपनी आय एवं कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए इन्हें अपनाया है। भारत को अपने कृषि क्षेत्र पर गर्व करवाने वाली आशाजनक प्रौद्योगिकियों के प्रभाव का प्रलेखीकरण करना महत्वपूर्ण है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग ने नास को परामर्शी कार्य का दायित्व सौंपा है। इसका उद्देश्य पिछली आशाजनक प्रौद्योगिकियों तथा उनके हस्तांतरण प्रयासों के एक ऐसे संग्रह को तैयार करना है जिनका दक्षता में सुधार, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने, किसानों की आय बढ़ाने, गरीबी कम करने, विदेशी मुद्रा सृजित करने तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

वर्ष 2021 के लिए नियोजित कार्यक्रम

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा प्रत्येक वर्ष भारतीय कृषि से सम्बद्ध राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर विचार-मंथन सत्र (बीएसएस), नीतिगत कार्यशालाओं (एसडब्ल्यू) का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2021 के लिए कार्यकारी परिषद ने निम्नलिखित कार्यक्रमों के आयोजन को मंजूरी दी है।

क्रम	विचार मंथन सत्र/नीतिगत कार्यशालाएं सं.	संयोजक/सह-संयोजक
1.	कृषि के रूपांतरण हेतु अनुबंध खेती: चुनौतियां एवं भावी मार्ग	डॉ. अंजनी कुमार
2.	बायोफार्मिंग के लिए ट्रांसजेनिक पोल्ट्री की क्षमता	डॉ. तरुण कुमार भट्टाचार्य
3.	बायोफोटिफिकेशन पर नीतिगत संवाद	डॉ. यू.एस. सिंह
4.	कृषि में लैंगिक एवं पोषण आधारित प्रसार	डॉ. अशोक के. सिंह
5.	डब्ल्यूटीओ एवं भारतीय कृषि	डॉ. पी.एस. बड़थल एवं सचिन के. शर्मा
6.	कठिन श्रम मुक्त कृषि	डॉ. एन. एस. बैंस एवं के. पी. सिंह
7.	वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर अपघटित भूमि के पुनर्वास हेतु योजना	डॉ. चौधरी श्रीनिवास राव, जे. सी. कत्याल, ए. के. सिंह
8.	पशु स्वास्थ्य एवं डेयरी उद्योग पर कोविड 19 का प्रभाव	डॉ. आर. के. सिंह एवं ए. के. सिंह
9.	कृषि विविधीकरण के उन्नयन हेतु गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री	डॉ. वी. के. बरनवाल
10.	कचरे से संपदा : पशु आहार के रूप में खाद्य उद्योग अपशिष्ट का उपयोग	डॉ. एन.के.एस. गौडा
11.	किसानों की आय में वृद्धि हेतु रेशमपालन	डॉ. एम. महादेवप्पा
12.	गुणवत्तायुक्त चारा उत्पादन हेतु कृषि एवं उद्यमिता मॉडल	डॉ. अजय कुमार रॉय

वित्तीय विवरण

अकादमी को कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डेयर), नई दिल्ली से वर्ष 2020–21 के दौरान 140 लाख रुपये का सहायता—अनुदान प्राप्त हुआ। अकादमी के खातों की लेखा संपरीक्षा राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के महा निकाय (जनरल बॉडी) के अनुमोदन से नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की जाती है। वर्ष 2020–21 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र, डेयर को प्रस्तुत कर दिया गया है।

वर्ष 2020–21 के लिए लेखा एवं लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के संक्षिप्त लेखा परीक्षित विवरण को अनुलग्नक I और II के रूप में संलग्न है किया गया है।

आभार

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (नास), कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा निरंतर वित्तीय एवं संचालन सहायता (लॉजिस्टिक) के लिए उनका आभार प्रकट करती है। अकादमी अन्य संगठनों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग और समर्थन के लिए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है।

अकादमी की प्रकाशन गतिविधियां मुख्य रूप से इसके प्रधान संपादक, संपादकों, सहयोगी संपादकों, सलाहकार मंडल, नास के पदाधिकारियों एवं कार्यकारी परिषद के सदस्यों तथा बड़ी संख्या में समीक्षकों (जो उन्हें भेजी गई पांडुलिपियों की जांच कर उन पर टिप्पणियां और सुझाव प्रदान करते हैं) के द्वारा प्रदत्त स्वैच्छिक एवं मानद सेवाओं के कारण सम्पन्न होती हैं। सम्मानित अध्येता, अकादमी की विभिन्न गतिविधियों जैसे वार्षिक आम सभा बैठक, शोध पत्रिकाओं की स्कोरिंग, नए फैलोशिप एवं अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकन की समालोचनात्मक जांच, कृषि विज्ञान कांग्रेस, विचार मंथन सत्र, नीतिगत कार्यशालाएं, संगोष्ठी एवं सार्वजनिक व्याख्यान, पारस्परिक विमर्श बैठकों के संचालन हेतु भी अपनी सेवाएं देते हैं। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, वर्ष के दौरान उपरोक्त गतिविधियों में शामिल अध्येताओं एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए उनका आभार प्रकट करती है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट



विरेन्द्र के. गुप्ता एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट

एम.सी.डी. बिलिंग, डी.बी. गुप्ता रोड,
पहाड़ गंज, नई दिल्ली – 110055
सम्पर्क : 98111427078 (का.) 43507900
ई-मेल : vkguptaca14@gmail.com

लेखापरीक्षक की स्वतंत्र रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,
राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी,
एनएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, पूसा,
नई दिल्ली – 110 012

हमने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली की 31 मार्च, 2021 तक के तुलन-पत्र और इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के आय एवं लेखा व्यय की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करना है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि हम यह ज्ञात करने के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि दी गई सामग्री या जानकारी किसी भी प्रकार के गलत विवरणों से मुक्त है और वित्तीय विवरण त्रुटिहीन हैं, इसका तर्कसंगत आश्वासन दिया गया है कि नहीं। हमारी लेखापरीक्षा में मैं परीक्षण के आधार पर वित्तीय लेन-देन के समर्थन में दिए गए प्रमाण तथा वित्तीय विवरणों के खुलासे शामिल हैं। हमारी इस लेखापरीक्षा में प्रयुक्त किए गए लेखा परीक्षा सिद्धांतों का मूल्यांकन करना और प्रबंधन द्वारा किए गए उल्लेखनीय आंकलनों के साथ सकल वित्तीय विवरणों के मौजूद होने का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा से हमारे विचारों को तर्कसंगत आधार मिलता है।

महत्वपूर्ण मामले

- प्रस्तुत लेखा (अकाउंट) का रखरखाव लगातार “नकद आधार” पर किया जा रहा है। हालांकि, बैंक व्याज आदि पर टीडीएस का दावा अक्रुअल बेसिस (उपार्जन आधार) पर किया गया है।



2. जीएसटी का भुगतान "उपार्जन आधार" पर किया गया है। जबकि लेखा का रखरखाव "नकद आधार" पर किया जा रहा है।

उपरोक्त के अलावा हमें यह भी सूचित करना है कि :

1. हमने वे सभी सूचनाएं एवं व्याख्याएं प्राप्त की हैं जो हमारे पूर्ण विवेक एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं।
2. जैसा कि नियमों में अपेक्षित है, हमारे विचार से अकादमी द्वारा उचित बहीखाते रखे गए हैं, जैसा कि इन बहीखातों की जांच से हमें प्रतीत हो रहा है।
3. इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र एवं आय व व्यय के लेखे अकादमी की लेखा बहियों में निर्धारित शर्तों के अनुरूप हैं।
4. हमारे विचार से इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय के लेखे यथासंभव लेखाकरण के मानकों का अनुपालन करते हैं।
5. हमारे विचार में और हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त लेखों का विवरण तथा उन पर दी गई टिप्पणियाँ और उनके साथ संलग्न किए गए दस्तावेज निम्नलिखित पर सत्य एवं सही विचार व्यक्त करते हैं :
 - (i) तुलन पत्र के मामले में अकादमी के मामलों की स्थिति 31 मार्च, 2021 तक की अवधि का है।
 - (ii) आय एवं व्यय के लेखों के मामले में समाप्त हुए वर्ष में आय से जो अधिक व्यय किया गया है, वह लेखाकरण की लेखा/पावतियों के आधार पर हुआ है जैसा कि राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा अपनाई गई लेखाकरण की प्रक्रियाविधि से स्पष्ट होता है।

विरेन्द्र के. गुप्ता एंड कंपनी की ओर से
चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन : 0000198 एन


(वी.के. गुप्ता)

साझेदार

एम. नं. 080585

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 16.07.2021

UDIN: 21080585AAAAB19769



राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (एनएएस)

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष

31 मार्च, 2021 को लेखा नीतियां एवं तुलनपत्र का हिस्सा बनने वाले लेखे पर टिप्पणियां

1. लेखाकरण की विधि

अकादमी लेखाकरण, आय एवं व्यय को नकद आधार पर अपना रही है इसलिए नकद/पावती आधार पर इसे मान्यता दी गई है।

2. निवेश

- (क) अकादमी ने अपने निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(5) के अंतर्गत निवेश की अपेक्षाओं के अनुसार किए हैं और निवेशों का मूल्य लागत पर दिखाया गया है।
- (ख) निवेशों से हुई आय को नकद/पावती के आधार पर मान्यता दी गई है।

3. अचल परिसम्पत्तियां और मूल्यहास

(क) अचल परिसंपत्तियां आयकर अधिनियम 1961 और उसके तहत बनाए गए नियमों के पाठ सहित उपलब्ध मूल्यहास की दरों के आधार पर गणना करने के पश्चात उनमें से मूल्यहास की राशि प्राप्त करके दर्शाए गए हैं।

4. आयकर के प्रावधान एवं आकस्मिक देयताएं :

(क) आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2016–17 में विर्निदिष्ट उद्देश्यों हेतु आय–संचय के लिए धारा 11(2) के तहत ₹ 3,91,85,233 के लाभ के दावे को अस्वीकार कर दिया है और ₹ 32,90,177 के रिफ़ंड के दावे को समायोजित करने के पश्चात ₹ 0 1,33,91,970 की मांग की है। इस अतिरिक्त राशि के विरुद्ध आयकर आयुक्त के समक्ष अपील दायर की गई है। प्रबंधन का यह मानना है कि कोई अतिरिक्त राशि नहीं बनती है इसलिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(ख) आयकर अधिकारी (ट्रस्ट), नई दिल्ली द्वारा 30.12.2019 को आयकर अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2017–18 के लिस कुल ₹ 0 1,11,91,925 की मांग करते हुए आयकर आदेश जारी किया गया है। इसके विरुद्ध सीआईटी (ए) दिल्ली के समक्ष अपील की गई है जिसकी सुनवाई अभी लंबित है। प्रबंधन का यह मानना है कि कोई अतिरिक्त राशि नहीं बनती है इसलिए मांग में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि, ग्रांट ऑफ स्टे के तौर पर ₹ 0 22,34,385 जमा करा दिए गए हैं।

5. विचाराधीन वर्ष के दौरान ₹ 0 3,11,76,115 की राशि का संचय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11(2) के तहत प्रस्तावित है।

6. लेखा परीक्षकों को भुगतान 31.3.2021 31.03.2020
लेखापरीक्षा शुल्क / जीएसटी शुल्क और व्यय 53,895/- 73,000/-

7. अन्य

- (क) प्रकाशनों की लागत उस वर्ष के दौरान चार्ज की गई है जिस वर्ष ऐसा व्यय किया गया है।
- (ख) अध्येतावृत्ति शुल्क से प्राप्त योगदान से हुई आय का नकद आधार पर लेखाकरण किया गया है।

विरेन्द्र के. गुप्ता एंड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(वी.के. गुप्ता)

साझेदार

एम. नं. 080585

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 16.07.2021



राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी



सचिव

कोषाध्यक्ष

वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 51

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी

31.03.2021 को शामाज्जर्व का तुलन पत्र (बँडेंस शीट)

देयताएं	राशि (रुपयों में)	परिसम्पत्तियां	राशि (रुपयों में)
पूरी निधि आदि शेष जमा : संचित निधि से हस्तांतरित जमा : वर्ष के दौरान योग की आक्षा हुई अधिक आय घटा : विशिष्ट आक्ष निधि से हस्तांतरित धनराशि विशिष्ट आक्षी निधि आदि शेष जमा : वर्ष के दौरान योग घटा : वर्ष के दौरान उपयोग की गई ^{एडब्ल्यूट (बंदोबस्ती) निधि} जमा: वर्ष के दौरान योग वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	15,60,82,451 1,59,59,181 1,86,85,761 3,11,76,115 15,84,15,684 3,11,76,115 1,59,59,181 20,00,000 —	अचल परिसम्पत्तियां (वार्षिक बैलेंस शीट 1) आदि शेष वर्ष के दौरान योग वर्ष के दौरान बहेखाते वर्ष के दौरान बहेखाते पर मूल्यदाता अनुमोदित सिक्योरिटी में जमा वर्तमान परिसम्पत्तियां बैंक में शेष राशि (वार्षिक बैलेंस शीट 3) नकद शेष राशि (इंग्रेस अकाउंट) अधिम (खड़वांसज) नास के क्षेत्रीय चेटरों को दी गई अधिम राशि चोत पर काटा गया कर (टीडीएस) आयकर विभाग को भुगतान निधिराशि वर्ष 2016-17 व 2017-18) प्राप्त योग्य जीएसटी (सीजीएसटी+एसजीएसटी)	1,86,74,576 47,182 — (20,80,022) 30,31,73,915 13,60,710 2 4,69,705 1,08,93,084 4,70,524 5,45,506 15,04,069 5,00,000 3,24,000 कुल
संलग्न टिप्पणियों का संदर्भ ले जो कि लेखा का एक भाग है हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न	33,85,27,995	कुल	33,85,27,995

विरेन्द्र के गुप्ता एवं कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(की. के. गुप्ता)
साझेदार
एम. नं. 080585
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 16.07.2021

संलग्न टिप्पणियों का संदर्भ ले जो कि लेखा का एक भाग है
हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी


Dr. S. C. Gupta

Dr. Rakesh Kapoor



UDIN: 21080585AAAAB19769

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (एनएसीआई)

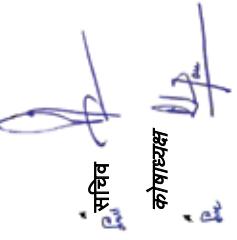
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का आय उंच व्यय लेखा

व्यय	राशि (रुपये में)	आय	राशि (रुपये में)
नास की गतिविधियों पर हुआ व्यय (वार्षिक आई.ई. 1)	1,59,11,999	डेपर से प्राप्त अनुदान सहायता के रूप में	1,40,00,000
मूल्यहास (वार्षिक बी.एस. 1)	20,80,022	निवेश पर प्राप्त व्याज के रूप में	2,07,56,250
व्यय से अधिक आय का स्थानांतरण	1,86,85,761	व्याज, अशदान, प्रकाशनों एवं नास के अन्य क्रियाकलापों से प्राप्त (वार्षिक आई.ई. III)	19,21,532
कुल	3,66,77,782	कुल	3,66,77,782

संलग्न विषयों का संदर्भ लें जो कि लेखा का एक भाग है
हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न

विरेन्द्र के. गुप्ता एंड कम्पनी
चाटर्ड अकाउंटेंट

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी




कार्यकारी परिषद

पद	2020	2021
अध्यक्ष	डॉ. टी. महापात्र	डॉ. टी. महापात्र
तात्कालिक भूतपूर्व अध्यक्ष	प्रोफेसर पंजाब सिंह	प्रोफेसर पंजाब सिंह
उपाध्यक्ष	प्रोफेसर ए. के. श्रीवास्तव	डॉ. जे. सी. कत्याल
अपाध्यक्ष	डॉ. जे. सी. कत्याल	डॉ. अनिल के. सिंह
सचिव	डॉ. अनिल के. सिंह	डॉ. पी.के. जोशी
सचिव	डॉ. पी.के. जोशी	डॉ. के. सी. बंसल
विदेश सचिव	डॉ. यू. एस. सिंह	डॉ. यू. एस. सिंह
संपादक	डॉ. कुसुमाकर शर्मा	डॉ. पी. एस. बर्थाल
संपादक	डॉ. पी. एस. बर्थाल	डॉ. मालविका ददलानी
कोषाध्यक्ष	डॉ. आर. के. जैन	डॉ. आर. के. जैन
सदस्य	डॉ. मधूलिका अग्रवाल	डॉ. मधूलिका अग्रवाल
सदस्य	डॉ. जे. एस. चौहान	डॉ. जे. एस. चौहान
सदस्य	डॉ. बी. एस. द्विवेदी	डॉ. एम.एस. चौहान
सदस्य	डॉ. अरविंद कुमार	डॉ. एस. के. दत्ता
सदस्य	डॉ. अश्विनी कुमार	डॉ. अरविंद कुमार
सदस्य	डॉ. डब्ल्यू. एस. लाकड़ा	डॉ. डब्ल्यू. एस. लाकड़ा
सदस्य	डॉ. वी. प्रकाश	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
सदस्य	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	प्रोफेसर ए. आर. पोडाइल
सदस्य	डॉ. डी. डी. पात्रा	डॉ. (मिस) तारु शर्मा
सदस्य	डॉ. ब्रह्म सिंह	डॉ. ब्रह्म सिंह
भा.कृ.अ.प. नामिति	डॉ. राजीव के. वार्ष्य	डॉ. राजीव के. वार्ष्य
	डॉ. आर. विश्वनाथन	डॉ. आर. विश्वनाथन
	डॉ. चौधरी श्रीनिवास राव	डॉ. चौधरी श्रीनिवास राव

सचिवालय

1. श्री संचल बिलग्रामी (31.05.2020 तक), कार्यकारी निदेशक
2. श्री मिराजउद्दीन, बजट एवं लेखा कार्यपालक
3. सुश्री मीनू तिवारी, प्रोग्राम कार्यपालक
4. श्री पी. कृष्णा, प्रोग्राम कार्यपालक
5. श्री उमेश राय, प्रोग्राम कार्यपालक
6. श्री जय सिंह, कार्यालय प्रबंधन कनिष्ठ कार्यपालक
7. श्री बी.एल. यादव, वाहन—चालक व सह कार्यालय सहायक
8. श्री कमल सिंह, सामान्य कार्यालय सहायक

संक्षिप्तियों की सूची

एनएएएस	राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी
एजीएम	वार्षिक महासभा
ईसी	कार्यकारी परिषद
एएमआर	प्रतिसूक्ष्मजैविक प्रतिरोध
एसओसी	मृदा कार्बनिक कार्बन
बीडीए	जैविक विविधता अधिनियम
पीवीवीएफआरए	पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम
सीजीआईएआर	अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर परामर्शक समूह
एसओपी	मानक परिचालनीय क्रियाविधियां
एआरसी	शीर्षस्थ जड़दार कलमें
सीएफएम	सांद्रित फल परिपक्वता
एमएच	यांत्रिक कटाई
टीएडी	सीमा पार पशु रोग
आरसीजीएम	आनुवंशिक फेरबदल पर समीक्षा समिति
जीईएसी	आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति
सीआईपी	अंतरराष्ट्रीय आलू केन्द्र
आईएमएसए	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी
एनएएसआई	राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत
इक्रीसेट	अंतरराष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधी फसल अनुसंधान संस्थान
एनएआरएस	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली
आईसीएआर—एनडीआरआई	भा.कृ.अ.प.—राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान
आईसीटी	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
एएससी	कृषि विज्ञान कांग्रेस
बीएचयू	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन

सीएनआरएस	राष्ट्रीय विज्ञान अनुसंधान केन्द्र
आईसीएआर—एसबीआई	भा.कृ.अ.प.—गन्ना प्रजनन संस्थान
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
आईसीएआर—नार्म	भा.कृ.अ.प.—राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी
आईएमएसए	भारतीय मांस विज्ञान एसोसिएशन
आईसीएआर—सीएसएसआरआई	भा.कृ.अ.प.—केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान
पीएयू	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय
एचपीकेवी	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय
आईसीएआर—एनआईएसएम	भा.कृ.अ.प.—राष्ट्रीय अजैविक प्रतिबल प्रबंधन संस्थान
एसएआरएस	कृषि विज्ञान में अजैविक प्रतिबल अनुसंधान सोसायटी
केआईआईटी	कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान
एनईपी	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
एसटीआईपी	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष कार्यक्रम
आईसीएमआर	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद
आईसीएआर—वीपीकेएस	भा.कृ.अ.प.—विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
एनईएच	पूर्वोत्तर पर्वत
सार्क	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन
आईसीएआर—एनआईएपी	भा.कृ.अ.प.—राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान संस्थान
एसडीजी	टिकाऊ विकास के लक्ष्य
सीएजी	भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक
एनएएससी	राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र
यूएवी	मानव रहित वायुवीय वाहन
पीएमएफबीवाई	प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना
बीएसएस	विचार मंथन सत्र
आईसीएआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
सीएसआईआर	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद

65. वलाइमेट रेजिलियन्ट एग्रीकल्वर इन इंडिया	2014
66. रोल ऑफ मिलेट्स इन न्यूट्रिशनल सेक्युरिटी ऑफ इंडिया	2014
67. अर्बन एंड पेरी अर्बन एग्रीकल्वर	2014
68. इफीसियेन्ट यूटीलाइजेशन ऑफ फॉर्सोरस	2014
69. कार्बन इकोनॉमी इन इंडियन एग्रीकल्वर	2014
70. डब्ल्यू फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन इंडियन एग्रीकल्वर : ऑपर्चूनीटिज एंड चैलेन्जिज	2014
71. रोल ऑफ रुट इन्डोफाइट्स इन एग्रीकल्वरल प्रोडक्टीविटी	2014
72. बायोइन्स्ट्रॉमेटिक्स इन एग्रीकल्वर : वे फॉर्मर्ड	2014
73. मॉनीटरिंग एंड इवेल्यूशन ऑफ एग्रीकल्वरल रिसर्च, एजुकेशन एंड एक्सटेंशन फॉर डेवलेपमेन्ट (AREE4D)	2015
74. बायोइंजेनेज़ : एन इको फ्रैण्डली टूल फॉर कॉम्पैटिंग वॉटरलॉगिंग	2015
75. लिंकिंग फार्मर्स विद मार्केट्स फॉर इनवेलूसिव ग्रोथ इन इंडियन एग्रीकल्वर	2015
76. बायो फ्यूल्स टू पॉवर इंडियन एग्रीकल्वर	2015
77. एक्वाकल्वर सर्टिफिकेशन इन इंडिया : क्राइटरिया एंड इम्पलीमेन्टेशन प्लान	2015
78. रिजरवॉयर फिशरीज़ डेवलेपमेन्ट इन इंडिया : मैनेजमेन्ट एंड पॉलिसी ऑष्ठान्स	2016
79. इन्डोग्रेशन ऑफ मेडीसिन एंड एरोमैटिक क्रॉप कल्टीवेशन एंड वैल्यू चैन मैनेजमेन्ट फॉर स्मॉल फार्मर्स	2016
80. ऑगमेन्टिंग फोरेज रिसोर्सिज इन रूरल इंडिया : पॉलिसी इश्वर्यूज एंड स्ट्रेटीजिज	2016
81. वलाइमेट रेजिलियन्ट लाइवस्टॉक प्रोडक्शन	2016
82. ब्रीडिंग पॉलिसी फॉर कैटल एंड बुफेल्लो इन इंडिया	2016
83. इश्यूज़ एंड चैलेन्जिज इन शिफिटंग कल्टीवेशन एंड इट्स रिलेवेन्स इन दि प्रेजेन्ट कॉनटेक्स्ट	2016
84. प्रैक्टीकल एंड एफॉर्डेबल एप्रोच्स फॉर प्रेसीजन इन फार्म इक्यूपमेन्ट एंड मशीनरी	2016
85. हाइड्रोपॉनिक फोर्डर प्रोडक्शन इन इंडिया	2017
86. मिसमैच विट्कीन पॉलीसिज एंड डेवलेपमेन्ट प्रायोरीटिज इन एग्रीकल्वर	2017
87. अबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेन्ट विद फॉकस ऑन ड्रॉट, फूड एंड हैलस्टॉर्म	2017
88. मिटीगेटिंग लैण्ड डिग्रेडेशन डग्यू टू वॉर्टर इरोजन	2017
89. वर्टीकल फार्मिंग	2019
90. जीरो बजट नेतुरल फार्मिंग – ए मिथ और रियलिटि?	2019
91. लोन वैरिंग वर्सज इनकम सपोर्ट स्कीम्स : बैरेंजेज एंड वे फॉरवर्ड	2019
92. ट्रायपिकल विल्ट रेस-4 अफेरिटिंग बनाना कल्टीवेशन	2019
93. कृषि विज्ञान के संस्थानों में विज्ञान संस्कृति का संबर्द्धन	2020
94. कृषि में पारिस्थितिकी सेवाओं का भुगतान	2020
95. खाद्य-जनित पशु रोग	2020
96. कृत्रिम गर्भधान द्वारा पशुधन में सुधार	2020
97. गैर-गोजातीय दूध की संभावना / क्षमता	2021
98. पॉच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए कृषि एवं खाद्य नीति	2021

स्थिति/कार्यनीति पत्र

1. रोल ऑफ सोशल साइन्टिस्ट इन नेशनल एग्रीकल्वरल रिसर्च सिस्टम (NARS)	2015
2. ट्रॉवर्ड्स पल्टिस सेल्फ सफीसियेन्सी इन इंडिया	2016
3. रस्ट्रैट्जी फॉर ट्रांसफार्मेन्ट एग्रीकल्वर एंड इम्प्रूविंग फार्मर्स वेल्फेयर	2016
4. सर्टेनिंग सोयाबीन प्रोडक्टीविटी एंड प्रोडक्शन इन इंडिया	2017
5. रस्ट्रन्ट्रिंग एग्रीकल्वरल एक्सटेंशन रिसर्च एंड एजुकेशन	2017
6. रस्ट्रैट्जी ऑन यूटीलाइजेशन ऑफ ग्लॉबकोनाइट मिनरल एज सोर्स ऑफ पोटेशियम	2017
7. वेजिटेबल ऑयल इकोनॉमी एंड प्रोडक्शन प्राब्लम्स इन इंडिया	2017
8. कन्जरवेशन पॉलीसीज फॉर हिल्स एंड महसीर	2018
9. एक्सेलिपरिंटिंग सीडी डिलीवरी सिस्टम्स फॉर प्राइमिंग इंडियन फार्म प्रोडक्टीविटी इनहैन्समेन्ट : ए रस्ट्रैटजिक व्यू प्वाइंट	2018
10. रिन्यूवेबल एनर्जी : ए न्यू पैराडिग्म फॉर ग्रोथ इन एग्रीकल्वर	2018
11. रूमेन माइक्रोबियोम एंड एमेलियोरेशन ऑफ मीथेन प्रोडक्शन	2018
12. हारनेसिंग फूल पोटेशियल ऑफ ए 1 एंड ए 2 मिल्क इन इंडिया : एन अपडेट	2018
13. डेवलेपमेन्ट एंड एडॉशन ऑफ नोवल फर्टिलाइजर मैटीरियल्स	2018

नीति संबंधी संक्षिप्त पत्र

1. टू एक्सीलरेट यूटीलाइजेशन ऑफ GE टेक्नोलॉजीज फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूविंग फार्मर्स इनकम	2016
2. इनोवेटिव वियेबल साल्यूशन टू राइस रेजिडू बर्निंग इन राइस – व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम थू कनकरेन्ट यूज ऑफ सुपर स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम – फिटिड कम्बाइन्स एंड टर्बो हैप्पी सीडर	2017
3. सॉयल वैल्श : न्यू पॉलिसी इनीशियेटिव्स फॉर फार्मर्स वेल्फेयर	2018
4. यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर फिश डिजीज डाग्नोसिस एंड कॉरनटाइन	2019
5. सेविंग दि हार्वेस्ट: रेड्सिंग दि फूड लोस एंड वेस्ट	2019
6. भारत में कीटनाशकों का बेहतर प्रबंधन : नीतिगत परिवृद्धश्य	2019
7. जीनोम संशोधित पौधों हेतु विनियामक तंत्र : पादप प्रजनन में सटीकता एवं गति को तेज करना	2020
8. कोविड-19 वैश्विक महामारी : प्रभाव एवं कृषि में नई प्रक्रियाएं (न्यू नार्मल)	2020
9. उर्वरक सहायता का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण : नीतिगत परिवृद्धश्य	2020
10. भारत में टिकाऊ खाद्य सुरक्षा हेतु बीज विनियमन में सामंजस्य	2020

नीतिगत मुद्दों पर नास दस्तावेज़*

1. एग्रीकल्वरल साइन्टिस्ट परसेप्सान्स ऑन नेशनल वॉटर पॉलिसी	1995
2. फर्टिलाइजर पॉलिसी इश्यूज (2000–2025)	1997
3. हारनेसिंग एंड मैनेजमेन्ट ऑफ वॉटर रिसोर्सिंग फॉर इन्हेन्सिंग एग्रीकल्वरल प्रोडक्शन इन दि ईस्टर्न रीजन	1998
4. कन्जरवेशन एंड मैनेजमेन्ट एंड यूज ऑफ एग्रीबायोडाइवर्सिटी	1998
5. सर्टेनेबल एग्रीकल्वरल एक्सपोर्ट	1999
6. रि-ओरियेन्टिंग लैण्ड ग्रांट सिस्टम ऑफ एग्रीकल्वरल एजुकेशन इन इंडिया	1999
7. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्वर फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन	2001
8. सर्टेनेबल फिशरीज एंड एक्वाकल्वर फॉर न्यूट्रिशनल सेक्युरिटी	2001
9. स्ट्रैटीजिज फॉर एग्रीकल्वरल रिसर्च इन दि नॉर्थ – ईस्ट	2001
10. ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्वर : आर एंड डी इन इंडिया	2001
11. इम्पारमेन्ट ऑफ वूमेन इन एग्रीकल्वर	2001
12. सैनीटरी एंड फाइटोसैनीटरी एग्रीमेन्ट ऑफ दि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन – एडवॉटेज इंडिया	2001
13. हाई-टेक हॉर्टीकल्वर इन इंडिया	2001
14. कन्जरवेशन एंड मैनेजमेन्ट ऑफ जिनेटिक रिसोर्सिंग ऑफ लाइवरस्टॉक	2001
15. प्रायोरिटीजेशन ऑफ एग्रीकल्वरल रिसर्च	2001
16. एग्रीकल्वर – इंडस्ट्री इन्टरफेस : वैल्यू एडिड फार्म प्रोडक्ट्स	2002
17. साइन्टिस्ट विश्यू ऑन गवर्नेंस ऑफ एन एग्रीकल्वरल रिसर्च ऑर्गनाइजेशन	2002
18. एग्रीकल्वरल पॉलिसी : रिडिजाइनिंग आर एंड डी टू एचीव इट्स ऑब्जेविट्स	2002
19. इन्टेरेक्वयूल प्राप्टी राइट्स इन एग्रीकल्वर	2003
20. डाइकोर्टोंमी विटवीन ग्रैन सरप्लस एंड वाइडस्ट्रेट इन्डीमिक हंगर	2003
21. प्रायोरिटीज ऑफ रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेन्ट इन किशरीज बायो टेक्नोलॉजी	2003
22. सीवीड कल्टीवेशन एंड यूटीलाइजेशन	2003
23. एक्सपोर्ट पोटेनशियल ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स	2003
24. बायोसेफ्टी ऑफ ट्रांसजेनिक राइस	2003
25. स्टैकोहल्डर्स परसेप्शन ऑन इम्पलॉयमेन्ट ओरियेन्टिंग एग्रीकल्वरल एजुकेशन	2004
26. पेरी अर्बन वैटिजेबल कल्टीवेशन इन दि एनसीआर दिल्ली	2004
27. डिजास्टर मैनेजमेन्ट इन एग्रीकल्वर	2004
28. इम्पैक्ट ऑफ इंटर रीवर बैसिन लिंकेज ऑन फिशरीज	2004
29. ट्रांसजेनिक क्रॉप्स एंड बायोसेफ्टी इश्यूज रिलेट्ड टू देअर कमर्शिलाइजेशन इन इंडिया	2004
30. ऑर्गेनिक एप्रोच्स एंड पॉसीविलीटीज इन दि आनटेक्स्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्वर	2005
31. री-डिफाइनिंग एग्रीकल्वरल एजुकेशन एंड एक्सपैटेशन सिस्टम इन चेन्जड सिनेरियो	2005
32. इमर्जिंग इश्यूज इन इंडिया : वैल्यू एंड रिसेप्शन ऑफ ऑनररिप	2005
33. पॉलिसी ऑसान्स फॉर इकोसियेन्ट नाइट्रोजन यूज	2005
34. गाइडलाइन्स फॉर इम्पैक्ट विश्यू एंड इंडियन जर्नल्स एंड प्रोफेशनल्स सोसायटीज इन एग्रीकल्वर एंड एलॉइड साइन्सिज	2006
35. लो एंड डिकलाइनिंग क्रॉप्स रिस्पोन्स टू फॉलिलाइजर्स	2006
36. बिलो ग्राउन्ड बायो डाइवर्सिटी इन रिलेशन टू क्रॉप्पिंग सिस्टम्स	2006
37. इम्पलॉयमेन्ट ऑपरेन्टिंग इन फार्म एंड नॉन कार्म सेक्टर्स थू टेक्नोलॉजिकल इन्टरवेनेशन्स विद इम्फेसिस ऑन प्राइमरी वैल्यू एडिशन	2006
38. डब्ल्यूटीओ एंड इंडियन एग्रीकल्वर : इम्पलॉकेशन्स फॉर पॉलिसी एंड आर एंड डी	2006
39. इनोवेशन्स इन रुरल इंस्टीट्युशन्स : ड्राइवर फॉर एग्रीकल्वरल प्रॉसैपरिटी	2007
40. हाई वैल्यू एग्रीकल्वर इन इंडिया : प्रॉसैपर्ट्स एंड पॉलीसिज	2008
41. सर्टेनेबल एनजी फॉर रुरल इंडिया	2008
42. क्रॉप्स रिस्पोन्स एंड न्यूट्रियेन्ट रेशियो	2009
43. एंटी-बायोटिक्स इन रेशियो एंड सॉसियल – ए ग्रेव थ्रेट टू ह्यूमन एंड एनीमल हैल्थ	2010
44. प्लांट कवारनाटाइन इन्वेन्ट्रॉडिंग इन्टरवेनेशन्स एक्वाकल्वर वियू ऑफ ऑनस्लॉट ऑफ डीजिज एंड इनसेक्ट पेस्ट्स	2010
45. एप्रो कैमीकल्स मैनेजमेन्ट : इश्यूज एंड स्ट्रैटीजिज	2010
46. वैटरनिरी वैक्सीन्स एंड डॉयगनोरिस्टर्स	2010
47. प्रोटेक्ट एग्रीकल्वर इन नॉर्थ वैस्ट हिमालयाज	2010
48. एक्सप्लोजिंग अनटेप्ट पोटेनशियल ऑफ एसिड सॉयल्स ऑफ इंडिया	2010
49. एग्रीकल्वरल वैस्ट मैनेजमेन्ट	2010
50. ड्रॉट एप्रेयर्डनेट एंड मिटीगेशन	2011
51. कैरीइंग कैपेसिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्वर	2011
52. बायोसेफ्टी एश्युरेन्स फॉर जीएम फूड क्रॉप्स इन इंडिया	2011
53. इकोलोबलिंग एंड सर्टिफिकेशन इन कैप्चर फिशरीज एंड एक्वाकल्वर	2012
54. इन्टीग्रेशन ऑफ मिलेट्स इन फॉर्टिफाइड फूड्स	2012
55. फाइटिंग चाइल्ड मलन्यूट्रिशन	2012
56. सर्टेनिंग एग्रीकल्वरल प्रॉडक्टीविटी थू इन्टीग्रेट्ड सॉयल मैनेजमेन्ट	2012
57. वैल्यू एडिड फॉलिलाइजर्स एंड साइट स्पेसीफिक न्यूट्रियेन्ट मैनेजमेन्ट (SSNM)	2012
58. सरक्षण कृषि के संदर्भ में फसल अवशेषों का प्रबंधन	2012
59. पशुओं में बांझापन एवं इसका प्रबंधन	2013
60. वॉटर यूज पोटेनशियल ऑफ फलड एफेक्टिव एंड ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ ईस्टर्न इंडिया	2013
61. मैसटीटिस मैनेजमेन्ट इन डेयरी एनीमल्स	2013
62. बायो पेरस्टीसाइड्स : क्वालिटी एश्युरेन्स	2014
63. नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्वर : रस्कोप एंड करन्ट रिलेवेन्स	2014
64. इम्पैक्ट एडवर्टीविटी ऑफ राइस फैलोज	2014